

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com

ग्वालियर, मंगलवार 22 सितंबर 2026 | वर्ष-08, अंक-161, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए

Website: www.eksatbulletin.in

पूरे देश को कब तबाह कर दूँ? ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ईरान पर बड़े हमले का विकल्प भी शामिल है। उन्होंने सवाल



किया, मैं पूरे देश को कब तबाह कर दूँ? ईरान को एक नई चेतावनी देते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि वह ईरान युद्ध को लेकर फैसला लेने की स्थिति में हैं और निकट भविष्य में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी ईरान के उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि उसने मध्यस्थों के जरिए होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए अपनी शर्तें अमेरिका तक पहुंचा दी हैं। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि वह फैसला लेने की स्थिति में हैं और निकट भविष्य में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। उन्होंने अपने सामने मौजूद विकल्पों में ईरान का सफाया करना, उसे आर्थिक रूप से बर्बाद होने देना या कूटनीतिक समझौता करना बताया है। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है कि अगर और कब मैं पूरे देश को तबाह कर दूँ? उन्हें बेहतर होगा कि वे सही व्यवहार करें। श्री ट्रंप ने गुरुवार को भी कहा था कि वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान में जाकर उसे पूरी तरह तबाह कर दूँ या नहीं।

उन्होंने कहा था कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। श्री ट्रंप की ताजा टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयन के इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचने की उम्मीद है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अन्य वरिष्ठ ईरानी अधिकारी भी उनके साथ आ सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरानी अधिकारियों के एक मुख्य प्रतिनिधिमंडल को महासभा के उच्चस्तरीय सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

दूसरे दिन भारत ने जीते चार पदक

निशानेबाजों ने कराई चांदी, सुविका तरियाल ने एमएमए में दिलाया मेडल



■ एजेन्सी, नई दिल्ली

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने एक साथ दो पदक अपने नाम किए। हिमांशु ढिल्लन ने रजत, जबकि रुद्राक्ष पाटिल ने कांस्य पदक जीता। हिमांशु ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे। वहीं, रुद्राक्ष 230.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। रुद्राक्ष पाटिल ने फाइनल में लंबे समय तक पदक की दौड़ में बढ़त बनाए रखी थी। वह लगातार स्वर्ण पदक की स्थिति में बने हुए थे, लेकिन बाद के दौर में चीन के शेन लिहाओ ने शानदार वापसी की। रुद्राक्ष पहले स्वर्ण पदक की स्थिति से नीचे आए और इसके बाद 9.7 के एक खराब शॉट के कारण तीसरे स्थान पर खिसक गए। इसके बाद उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने एक साथ दो पदक अपने नाम किए। हिमांशु ढिल्लन ने रजत, जबकि रुद्राक्ष पाटिल ने कांस्य पदक जीता। हिमांशु ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे। वहीं, रुद्राक्ष 230.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। रुद्राक्ष पाटिल ने फाइनल में लंबे समय तक पदक की दौड़ में बढ़त बनाए रखी थी। वह लगातार स्वर्ण पदक की स्थिति में बने हुए थे, लेकिन बाद के दौर में चीन के शेन लिहाओ ने शानदार वापसी की। रुद्राक्ष पहले स्वर्ण पदक की स्थिति से नीचे आए और इसके बाद 9.7 के एक खराब शॉट के कारण तीसरे स्थान पर खिसक गए। इसके बाद उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

सभी शासकीय भवनों पर स्थापना दिवस पर एक नवम्बर की रात्रि को की जाएगी रोशनी

समृद्ध किसान – समृद्ध प्रदेश की थीम पर मनाया जाए प्रदेश का स्थापना दिवस : सीएम डॉ. यादव

कृषि पर केन्द्रित होंगी प्रदर्शनियां और कृषि के क्षेत्र में नवाचार व उपलब्धियों को मिलेगा सम्मान

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2026 समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश की थीम पर किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। एक नवम्बर को वर्ष 2026 का मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कृषि विकास और किसान कल्याण पर केन्द्रित हो। उन्नत कृषि, प्राकृतिक खेती, कृषि में नवाचार आदि पर विशेष रूप से प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं तथा कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने और उपलब्धियां अर्जित करने वाले कृषकों, उद्यमियों, युवाओं को सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर गतिविधियों के साथ ही जिलों में भी उत्साह और उल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सभी शासकीय भवनों पर स्थापना दिवस पर एक नवम्बर की रात्रि में रोशनी की जाए।

प्रदेश की प्रतिभाओं को अपनी कला, योग्यता और क्षमता के प्रदर्शन का मौका प्रदान करने के लिये कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। स्थापना दिवस समारोह प्रदेश का उत्सव है। राज्य और जिलास्तरीय कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये निर्देश मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के संबंध में आज मंत्रालय में हुई बैठक में दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अशोक बर्गवाल, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन, श्री संजय कुमार शुक्ला, श्री शिवशेखर शुक्ला, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित संस्कृति तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि 71वें मध्यप्रदेश स्थापना समारोह का राज्य स्तरीय समारोह लाल परेड ग्राउंड में होगा।



जिले की उपलब्धियों को किया जाए प्रदर्शित

स्थापना दिवस समारोह में जिला मुख्यालयों पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां, जिलावार उत्कृष्ट कार्यों और जिला उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, उद्योगपतियों, व्यवसायियों, धर्मगुरुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों, शहीद सैनिकों के परिजन और महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित करने वाले स्व-सहायता समूहों, स्टार्ट-अप से जुड़े व्यक्तियों की विशेष रूप से आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए बैठक व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा व्यवस्था आदि के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके अंतर्गत विकसित मध्यप्रदेश-2047, एक जिला-एक उत्पाद, मध्यप्रदेश के जननायक, प्रदेश की पारम्परिक कलाओं, मंदिर स्थापत्य, भारत की ऋषि परम्परा, प्रदेश में विरासत से विकास और कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियों पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी।

इस अवसर पर देशज व्यंजनों का मेला भी विशेष रूप से होगा। एक नवम्बर की शाम को भव्य स्तर पर सुगम संगीत पर कार्यक्रम होगा। इसमें देश के प्रतिष्ठित कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर आकर्षक आतिशबाजी भी की जाएगी।

मिडल ईस्ट में तनाव से अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन में बिगड़े हालात

डीजल की कीमतों ने तोड़े रिकॉर्ड सूखा पड़ा हर नौवां पेट्रोल पंप

■ एजेन्सी, नई दिल्ली

मिडल ईस्ट में अमरीका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की आपूर्ति ठप होने से वैश्विक स्तर पर ईंधन का महासंकट खड़ा हो गया है। अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई विकसित देश रिकॉर्ड तोड़ ईंधन कीमतों और आपूर्ति की किल्लत से जूझ रहे हैं। कई देशों में डीजल की भारी किल्लत हो गई है। कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं।

अमरीका में दोगुना हुई डीजल की कीमतें

अमरीका में डीजल की राष्ट्रीय औसत कीमत 6.49 डॉलर (करीब 622 रुपए) प्रति गैलन के आँल-टाइम हाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मिडल ईस्ट संकट शुरू होने से ठीक पहले 27 फरवरी



फ्रांस के 11 फीसदी पेट्रोल पंप पर तेल खत्म

फ्रांस में ईंधन संकट इतना गहरा गया है कि देश का हर नौवां पेट्रोल पंप (लगभग 11 फीसदी) सूखा पड़ चुका है। कई क्षेत्रों में 16 फीसदी तक स्टेशनों पर ईंधन खत्म हो चुका है। फ्रांस में डीजल की औसत कीमत 2.39 यूरो (करीब 264 रुपए) प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई है। देश के 700 से अधिक पंपों पर प्रीमियम ग्रेड ईंधन 2.50 यूरो (करीब 276 रुपए) से 2.70 यूरो (करीब 298 रुपए) प्रति लीटर तक बिक रहा है।

को डीजल की कीमत 3.75 डॉलर (करीब 360 रुपए) प्रति गैलन थी। यानी पिछले कुछ महीनों में इसमें 73 फीसदी की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैलिफोर्निया राज्य में डीजल 8.41 डॉलर (करीब 807 रुपए) प्रति

गैलन और पेट्रोल 6.13 डॉलर (करीब 588 रुपए) प्रति गैलन तक पहुंच गया है। अमेरिका का पूरा फ्रेट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क डीजल पर निर्भर है। ऐसे में खाद्यान्न और माल ढुलाई की लागत आसमान छू रही है।

भाजपा ने साधा निशाना- मेनेज था कार्यक्रम

'छात्रों की गूंज' में सवाल पूछने वाली निकली कांग्रेसी नेता

■ एजेन्सी, उज्जैन

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर दौरे के दौरान आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब विवादों के घेरे में आ गया है। दावा किया गया था कि यह कार्यक्रम पूरी तरह गैर-राजनीतिक रहेगा और इसमें केवल आम विद्यार्थी ही अपनी समस्याएं साझा करेंगे। हालांकि मंच पर पीएचडी छात्रा बनकर सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली उज्जैन की राधा मालवीय की राजनीतिक पृष्ठभूमि सामने आने के बाद प्रदेश में नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान राधा मालवीय ने पीएचडी विद्यार्थियों के आवास और किराए का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी से सवाल किया था कि जब उद्योगों को एक रुपये में लीज पर जमीन दी जा सकती है तो विद्यार्थियों को एक रुपये में कमरा क्यों नहीं दिया जा



सकता....? बाद में खुलासा हुआ कि राधा मालवीय महज एक छात्रा नहीं बल्कि उज्जैन से जिला पंचायत सदस्य, युवा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और शाजपुर जिला प्रभारी भी हैं। इस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। वहीं कांग्रेस के भी कई युवा कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर अंदरूनी नाराजगी देखी जा रही है।

इसी बीच राधा मालवीय की राजनीतिक पृष्ठभूमि सामने आने के बाद भाजपा ने कार्यक्रम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने तय किए नियम : दोबारा पकड़ने से पहले मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी

गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई तो एक्शन गैरकानूनी

■ एजेन्सी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी की वजह लिखित में बताना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है और जांच एजेंसी उसे दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस सीधे उसे नहीं पकड़ सकती। इसके लिए पहले मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होगी। दोबारा गिरफ्तारी की स्थिति में मामले की आगे की जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंपी जाएगी। कोर्ट ने ये टिप्पणियां शिरोमणि अकाली दल से जुड़े मुल्लापुर दाखा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी जसरकरनजीत सिंह की अपील पर कीं। नाबालिग

से यौन अपराध के आरोपों से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी की वजह लिखित में नहीं बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी माना। सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें स्थानीय अदालत के उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताने और तत्काल रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।

SC बोला- गिरफ्तारी की वजह समझ आने वाली भाषा में लिखित देनी होगी

जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अनुल चंद्रकुर की बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत आरोपी को गिरफ्तारी की वजह लिखित में और ऐसी भाषा में बतानी होगी, जिसे वह समझ सके। इसकी कॉपी भी उसे जल्द से जल्द देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्ति का मौलिक और वैधानिक अधिकार है। इसका उल्लंघन होने पर गिरफ्तारी



असंवैधानिक हो जाएगी और आरोपी को तत्काल रिहाई का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण व्यक्ति को रिहा किया जाता है

दोबारा गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अन्य बड़े निर्देश

जांच दूसरे अधिकारी को सौंपी जाएगी: सीनियर अधिकारी मामले की आगे की जांच किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को सौंपेगा। पहली गिरफ्तारी में गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होगी। गलती साबित होने पर कार्रवाई होगी और सर्विस बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। चार्जशीट से गिरफ्तारी वैध नहीं होगी: बाद में चार्जशीट दाखिल करने या कोर्ट के सज्ञान लेने से गैरकानूनी गिरफ्तारी सही नहीं हो जाएगी। आरोपी को नुकसान साबित करने की जरूरत भी नहीं होगी। अनुच्छेद 22(1) सभी गिरफ्तारियों पर लागू: अनुच्छेद 22(1) सामान्य और विशेष, दोनों तरह के मामलों में हुई गिरफ्तारियों पर लागू होता है। कोर्ट ने इसे मौलिक संवैधानिक सुरक्षा बताया। रिहाई को जमानत नहीं माना जाएगा: अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन पर रिहाई को जमानत नहीं माना जाएगा। इसे गैरकानूनी हिरासत से रिहाई माना जाएगा। अनुच्छेद 22(2) के उल्लंघन पर भी दोबारा हिरासत मांगने के लिए यही प्रक्रिया अपनानी होगी। जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट सुआवजा भी दे सकता है।

और जांच एजेंसी को उसकी हिरासत जरूरी लगती है, तो दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी देनी होगी। अर्जी में ये 3 बातें बतानी होंगी:

दोबारा गिरफ्तारी की वजह और उसकी जरूरत। पहली बार गिरफ्तारी के समय कारण क्यों नहीं बताए गए। आरोपी को गिरफ्तारी की वजह लिखित में देने के बाद ही अर्जी दाखिल की जाएगी। पहली

गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी दोबारा गिरफ्तारी का फैसला नहीं लेगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस अधिकारी ने पहली गिरफ्तारी में संवैधानिक नियम का उल्लंघन किया, उसे दोबारा गिरफ्तारी का फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दोबारा गिरफ्तारी की अर्जी पर उसके सीनियर अधिकारी की सहमति भी जरूरी होगी।

न्यूज ब्रीफ

दशलक्षण महापर्व में उत्तम सत्य धर्म की आराधना

जबलपुर। दशलक्षण महापर्व के पांचवें दिन रविवार को श्री 1008 महावीर स्वामी दिगम्बर जिनमंदिर, धर्मायतन, गोल बाजार में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ उत्तम सत्य धर्म की आराधना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक महोत्सव में सहभागिता कर भगवान जिनेंद्र देव का पूजन-अर्चन किया। महापर्व के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन के अंतर्गत रविवार रात 10 बजे ‘मृगावती—बैर का विसर्जन’ नाट्य प्रस्तुति का मंचन किया गया। भावपूर्ण अभिनय और प्रभावी संवादों के माध्यम से वैर, प्रतियोगिता और मोह से उत्पन्न परिस्थितियों तथा उनके आध्यात्मिक समाधान को प्रस्तुत किया गया। नाटक में संदेश दिया कि वास्तविक विजय दूसरों को पराजित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के वैर और विकारों का विसर्जन करने में है। नाट्य प्रस्तुति में क्षमा, संयम, करुणा और आत्मचिंतन को प्रमुखता दी। दशलक्षण महापर्व के अवसर पर प्रतिदिन प्रातः और रात्रि 9 से 10 बजे तक मुंबई से पधार विद्वान पंडित श्री विपिन शास्त्री के सानिध्य में शास्त्र स्वाध्याय कराया जा रहा है। 125 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी जिनबिंबों का सामूहिक वार्षिक जलाभिषेक किया जाएगा। 127 सितंबर, रविवार को पाटन रोड स्थित ‘ज्ञानायतन’ जिनमंदिर में क्षमावाणी पर्व का भव्य आयोजन होगा। इसमें जबलपुर के जैन परिवार परस्पर क्षमा मांगने और क्षमा प्रदान करने के साथ मैत्री, सद्भाव एवं आत्मशुद्धि का संदेश देंगे। सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन श्री वीतराग विद्वान मंडल एवं जैन युवा फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे हैं।

आउटसोर्स कर्मचारियों को 7 तारीख तक मिले वेतन

जबलपुर। जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विभागों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों तथा निजी प्रतिष्ठानों में आउटसोर्स या ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सहायक श्रम आयुक्त सूर्यकांत सिरवैया ने सभी नियोजकों को निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों का लाभ और समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। जारी आदेश के अनुसार वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत 1,000 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान होना आवश्यक है। श्रम विभाग ने सभी विभाग/प्राध्यापकों और एजेंसियों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिला है या नहीं, इसकी मासिक रिपोर्ट हर महीने की 7 तारीख तक श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करें। इसके साथ ही सविदा श्रम अधिनियम, 1970 के अंतर्गत विभाग और आउटसोर्स ठेकेदार दोनों का पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है। श्रम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि औचक निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी संस्थान या ठेकेदार द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

‘2222 गैंग’ के नाम से रील बना रहा था, जबलपुर की तिलवारा पुलिस ने दबोचा, बटनदार चाकू बरामद



जबलपुर। तिलवारा पुलिस ने सोशल मीडिया पर चाकू के साथ रील बनाकर प्रसारित करने वाले एटाछेड़ा निवासी संजय उड्डे के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से अवैध बटनदार चाकू बरामद किया है। खुलेआम चाकू लहराते हुए नजर आ रहा था आरोपी सोशल मीडिया पर ‘2222 गैंग’ के नाम से वीडियो और रील बनाकर प्रसारित कर रहा था। इसमें वह खुलेआम चाकू लहराते हुए नजर आ रहा था। साइबर सेल की निगाह आरोपित की गतिविधियों पर पड़ी पुलिस की साइबर सेल की निगाह आरोपित की गतिविधियों पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने उसके संबंध में जानकारी जुटाई। पुष्टि होने पर तिलवारा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से बटनदार चाकू बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पूछताछ और कार्रवाई के बाद उसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

जब एक चौकीदार कुलसचिव कार्यालय में पहुंच गया, मुख्यालय कटनी स्थित व्यंकटेश लाइब्रेरी भेजा

कार्यालय में शराब के नशे में पहुंचा चौकीदार, अभद्रता करने पर निलंबित

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सोमवार सुबह उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब एक चौकीदार कुलसचिव कार्यालय में पहुंच गया। कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल के अनुसार कर्मचारी नशे की हालत में था और उसने अभद्र व्यवहार करते हुए हाथपाई का प्रयास किया। कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने चौकीदार रविन्द्र तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उसका मुख्यालय कटनी स्थित व्यंकटेश लाइब्रेरी निर्धारित किया गया है। कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल ने कहा कि रविन्द्र तिवारी के खिलाफ पहले भी सहायक कुलसचिव से



मारपीट का मामला सामने आ चुका है और इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। उनका कहना है कि लगातार इस तरह की घटनाओं को देखते हुए इस बार कठोर

कार्रवाई जरूरी थी। इसी आधार पर निलंबन के साथ उसका मुख्यालय भी कटनी किया गया है। दो कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस इसी बीच एक अन्य मामले में

चोरी की गई रेल संपत्ति बरामद

ट्रेन के नीचे घुसकर काट रहे थे बैटरी की वायरिंग, कबाड़ी सहित तीन गिरफ्तार

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

अधारताल स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों को निशाना बनाकर बैटरियां चोरी करने वाले गिरोह का रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने पर्दाफाश किया है। आरपीएफ जबलपुर पोस्ट की टीम ने ट्रैक पर खड़े कोचों के नीचे घुसकर बैटरियों की वायरिंग काट रहे दो आरोपियों को रोहथ पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि चोरी का माल एक कबाड़ी को बेचा जाता था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों के कब्जे से चोरी की गई रेल संपत्ति बरामद की गई है। आधारताल स्टेशन एवं यार्ड क्षेत्र में स्टेबल ट्रेनों से बैटरियां चोरी होने की सूचना के बाद विशेष निगरानी बढ़ाई गई थी। प्रभारी निरीक्षक राजीव खरब ने निर्देशन में उप निरीक्षक आरके चंदेल, प्रधान आरक्षक जितेंद्र तिवारी और आरक्षक हरिकेश को टीम लगातार गश्त कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि नजर आई। टीम ने देखा कि दो युवक स्टेबल कोचों के नीचे घुसकर बैटरियों की वायरिंग काट रहे हैं। घेराबंदी कर दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान चारखंबा छोटी मदार टेकरी निवासी राशिद अली (30) और ठक्कर ग्राम पंचकुईया निवासी मोहम्मद बसीम (26) के रूप में हुई।



दोनों से पूछताछ के बाद आरपीएफ ने चोरी का माल खरीदने वाले साजिद अंसारी (25) को पकड़ा। साजिद मूलतः कुंडम के वार्ड नंबर आठ का निवासी है जो कि अभी ठक्कर ग्राम में रह रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरपीएफ जबलपुर पोस्ट प्रभारी राजीव खरब ने बताया कि तीनों आरोपियों पर रेल संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने स्टेशन, यार्ड या पटरियों के आसपास संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल आरपीएफ को सूचना देने कहा है। इसे देखते हुए आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक राजीव खरब के निर्देशन में विशेष टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम ने देखा कि कुछ युवक ट्रेन

के कोचों के नीचे छिपकर बैटरी की वायरिंग काट रहे हैं। मुस्तैद जवानों ने तुरंत घेराबंदी कर दो युवकों को मौके पर ही दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राशिद अली (निवासी चारखंबा छोटी मदार टेकरी) और मोहम्मद बसीम (निवासी ठक्कर ग्राम पंचकुईया) के रूप में हुई है। कबाड़ी भी चढ़ा हथ्यपकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आया कि वे चोरी की गई रेल संपत्ति और कॉपर/बैटरी वायरिंग को कबाड़ी के पास बेचते थे। आरोपियों की निशानदेही पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी साजिद अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया है।

कतिया समाज स्वसहायता संघ जबलपुर की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ



■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

कतिया समाज स्वसहायता संघ जबलपुर की दिनांक 20.09.2026 को आयोजित वार्षिक आमसभा में सर्वश्री के आर ब्रम्हे -अध्यक्ष, नरेश बनारिया - उपाध्यक्ष, लेखराम भोर महासचिव, जगदीश प्रसाद प्यारे संयुक्त सचिव, डी पी शिववेदी कोषाध्यक्ष, एवं कार्यकारिणी सदस्यों में श्री राकेश कुमार नाग,

वीरेंद्र कुमार गौतम, बी एल नागेश, रतन नागेश, सोन सिंह सोनगोत्रा, श्रीमती अर्चना सिसोदिया निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाचन कार्य को मुख्य चुनाव अधिकारी श्री सुरेश नाग, चुनाव अधिकारी श्री गोविन्द प्रसाद नागवंशी खंडवा एवं चुनाव पर्यवेक्षक श्री घनश्याम प्रसाद सिंगोतिया द्वारा दायित्व का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

निर्धारित राशि से अधिक नकदी मिलने पर तत्काल निलंबित

जबलपुर में विजिलेंस का छापा, ट्रेन से उतरते ही दो टीटीई की जेब से मिली अतिरिक्त राशि

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जबलपुर पहुंचते ही रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। पश्चिम मध्य रेलवे की विजिलेंस टीम ने प्लेटफार्म क्रमांक छह पर ट्रेन से इ्यूटी पूरी कर उतरते तीन टीटीई को रोककर उनकी तलाशी ली। जांच में दो टीटीई के पास निर्धारित राशि से अधिक नकदी मिलने पर दोनों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। तीसरे टीटीई की भूमिका की जांच जारी है। ट्रेन क्रमांक 22182 के जबलपुर पहुंचने से पहले ही विजिलेंस टीम मुख्य स्टेशन पर तैनात थी। ट्रेन के पहुंचते ही टीम ने इ्यूटी से उतरते टीटीई गुंजन कुमार, लक्ष्मी नारायण और महेंद्र मोघा को रोक लिया। तलाशी

लेने पर गुंजन कुमार के पास 58 सौ रुपये और लक्ष्मी नारायण के पास दो हजार रुपये अतिरिक्त मिले। वहीं टीटीई महेंद्र मोघा के पास अतिरिक्त राशि नहीं मिली। जबलपुर रेल मंडल ने दोनों टीटीई को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रेल विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि ट्रेन में टिकट जांच के दौरान यात्रियों से निर्धारित राशि से जबरन अधिक राशि ली जा रही है। टीटीई अवैध कमाई कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान अतिरिक्त नकदी मिलने के बाद तीनों टीटीई को सीटीआई कक्ष में ले जाकर आगे की कार्यवाही की गई। विजिलेंस टीम को तलाशी के दौरान तीसरे टीटीई महेंद्र मोघा के पास



अतिरिक्त राशि नहीं मिली। इस पर जांच अधिकारियों को संदेह है कि उसने बचने के लिए कहीं रुपये फेंक तो नहीं दिए। इसकी पुष्टि के लिए स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकाली

जा रही है। वह अभी संदेह के घेरे में है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में विजिलेंस (सतर्कता) टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ट्रेन संचालन के दौरान यात्रियों से अवैध

वसूली और टिकट जांच में अनियमितता की शिकायतों के आधार पर विजिलेंस टीम ने आचानक छापा मारा। इस कार्रवाई में ट्रेन से उतरते ही दो टीटीई की तलाशी ली गई, जिनकी जेब से भारी मात्रा में अतिरिक्त और अघोषित नकदी बरामद हुई है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विजिलेंस टीम को लंबे समय से इन दोनों टीटीई के खिलाफ अनधिकृत रूप से यात्रियों को बर्थ आवॉलेंट करने और रसीद दिए बिना जुर्माना वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। इसी सूचना के आधार पर विजिलेंस ने गोपनीय योजना बनाई। जैसे ही संबंधित ट्रेन जबलपुर स्टेशन पर पहुंची और दोनों टीटीई इ्यूटी पूरी कर नीचे उतरे, सतर्कता टीम ने उन्हें घेर लिया। टीम ने जब दोनों टीटीई की व्यक्तिगत

तलाशी ली, तो उनके पास से शासकीय कार्य से इतर भारी मात्रा में नकदी (कैश) मिली, जिसका वे कोई संतोषजनक हिसाब या वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह राशि यात्रियों से अनधिकृत वसूली करके जुटाई गई थी। विजिलेंस टीम ने नियमों के तहत पूरी राशि को जब्त कर लिया है। विजिलेंस टीम ने दोनों टीटीई को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इस मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी गई है, जिसके बाद दोनों भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई और निलंबन की गाज गिरना तय माना जा रहा है। रेलवे प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से टीटीई लांबी में हड़कंप मच गया है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने महाराजा बाड़ा मल्टीलेवल कार पार्किंग का किया निरीक्षण

जनता के पैसे का एक-एक पैसा कार्य में लगे, कोई समझौता न हो: सिंधिया

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के प्रमुख केंद्र महाराजा बाड़ा में बन रहे मल्टीलेवल कार पार्किंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा विशेष रूप से बेसमेंट-3 में पानी की समस्या और उसकी निकासी की व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिला प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जनता के पैसे का एक-एक पैसा गुणवत्तापूर्ण कार्य में उपयोग होना चाहिए। विकास कार्यों में गति जरूरी है, लेकिन गुणवत्ता और निर्माण की सावधानियों से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बेसमेंट-3 में पानी की निकासी के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे विषय का समग्र एवं तकनीकी अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि पानी के आउटलेट और निकासी



व्यवस्था का ऐसा स्थायी एवं सुरक्षित समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों को इस विषय की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि महाराजा बाड़ा मल्टीलेवल कार पार्किंग ग्वालियर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। स्मार्ट

सिटी योजना के तहत विकसित की जा रही इस परियोजना से महाराजा बाड़ा क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में आवश्यक गति लाने के साथ गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए। परियोजना के तहत लगभग 77 करोड़ रुपये की लागत से 429 वाहनों की पार्किंग क्षमता विकसित की जा रही है। इसमें 353 चार-पहिया



और 76 दो-पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने निर्देश दिए कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का कार्य जनवरी-फरवरी 2027 तक पूरा करने की दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि पानी, सड़क और बिजली

जैसी बुनियादी सुविधाएं सीधे आमजन के जीवन से जुड़ी हैं। जिनका लाभ लंबे समय तक आम नागरिकों को मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का अंतिम उद्देश्य जनता की सेवा, बेहतर सुविधाएं और ग्वालियर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है।

शताब्दीपुरम दशहरा मैदान में चेतना मंच के 22वें भव्य दशहरा समारोह का भूमि पूजन संपन्न

नयी पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का सराहनीय कार्य कर रही है चेतना मंच: सतीश सिकरवार

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।

‘असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पर्व पर आयोजित होने वाले चेतना मंच के विशाल दशहरा समारोह की पूरे नगर में एक विशेष और अनूठी पहचान है। यहाँ मंचित होने वाली नृत्य नाटिका ‘कथा श्रीराम की’ प्रभु की अनन्य लीलाओं की एक जीवंत और अद्भुत प्रस्तुति होती है। ‘यह विचार क्षेत्रीय विधायक श्री सतीश सिकरवार ने आज शताब्दीपुरम स्थित दशहरा मैदान में व्यक्त किए। वे चेतना मंच द्वारा आयोजित किए जाने वाले 22वें दशहरा समारोह के भूमि पूजन के पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती रेखा त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष दीपक तोमर एवं संरक्षक ब्रजेश यादव विशेष रूप से गरिमामय उपस्थिति में मंच पर विराजमान रहे। विधायक सतीश सिकरवार ने चेतना मंच की सराहना करते हुए आगे कहा कि, ‘मैंने इस ऐतिहासिक दशहरा



समारोह के आयोजन को साल-दर-साल निरंतर आगे बढ़ते और भव्य होते देखा है। सफलता के 22वें पायदान पर पहुँचने के लिए पूरी चेतना मंच की टीम बधाई की पात्र है।’ उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि यहाँ आयोजित होने वाली

‘कथा श्रीराम की’ एक विशिष्ट आयोजन है, जिसमें 100 से अधिक स्थानीय कलाकार और युवा मंचन करते हैं। इसके माध्यम से वे सीधे रामायण के आदर्शों से जुड़ते हैं। नई पीढ़ी को अपनी सनातनी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास

से जोड़ने का जो अनुकरणीय कार्य चेतना मंच कर रहा है, वह वास्तव में वंदनीय है। कार्यक्रम के शुभारंभ पर चेतना मंच के पदाधिकारियों और वरिष्ठ सदस्यों ने अतिथियों का फूल-मालाओं से आत्मीय स्वागत किया। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से दीपक तोमर, ब्रजेश दीक्षित, ब्रजेश यादव, राम प्रकाश परमार, पीएस कुशवाहा, मूलचंद्र रसेनिया, बालकृष्ण शर्मा, गिरांश शर्मा, सागर नाठी, अभिषेक खडेलवाल, श्रीमती शालिनी गुप्ता, पूनम परिहार, अनिल शर्मा, जेपी पांडेय, विकास अग्रवाल, संतोष गुप्ता, सरिता शर्मा, रेखा तोमर, नरेश तोमर, रघुपाल यादव, दिनेश पटेल, कार्तिकेय यादव एवं ब्रजेश चतुर्वेदी आदि गणमान्य नागरिक शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत भाषण क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती रेखा त्रिपाठी ने दिया। मंच का कुशल व सफल संचालन बृजकिशोर दीक्षित ने किया तथा कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी अतिथियों व जनसमुदाय का आभार प्रदर्शन श्रीमती शालिनी गुप्ता द्वारा व्यक्त किया गया।

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।

सेवा-संकल्प अभियान’ को गंभीरता से ले और इसकी प्रत्येक गतिविधि का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों में ‘मेरे सपनों का भारत’, आंगनबाड़ियों में ‘आंगन मिलन सेवा’, विभिन्न स्थानों पर ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’, ‘सेवा सेतु’ का आयोजन प्रभावी ढंग से हो। साथ ही ‘सेवा मेरा योगदान’ के लिये शासन द्वारा निर्धारित 25 गतिविधियों में से कम से कम 10 गतिविधियों को प्रभावी रूप से मूर्तरूप दिया जाए। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में सेवा-संकल्प अभियान की समीक्षा

के दौरान विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने अभियान में जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने 100 दिन से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी शिकायतों का अभियान चलाकर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने शिकायतों के निराकरण में केवल संख्या पूरी करने के बजाय आवेदकों की संतुष्टि और समस्या के वास्तविक समाधान पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया।

उत्तम संयम का मार्ग सबसे कठिन होता है बिना संयम का मनुष्य पशु के समान है : आचार्य श्री

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

पर्युषण महापर्व पर आत्म साधना वर्षायोग समिति तथा सकल जैन समाज के तत्वावधान में आचार्य श्री चैत्य सागर महाराज एवं मुनिश्री अनुमान सागर महाराज ससंघ के सानिध्य में पर्युषण महापर्व के छठवें दिन आज सोमवार को दाना ओली स्थित दिगम्बर बीस पंथी चंपाबाग जैन मंदिर में उत्तम संयम धर्म का गुणगान कर भक्ति आराधना जैन समाज के लोगो ने दश लक्षण पूजन में भगवान जिनेंद्र के समझ महा अर्घ्य समर्पित कर की गई। वही 22 सितंबर मंगलवार को उत्तम तप की पूजन आराधना होगी। संयम धर्म पर किया श्रीजी का अभिषेक, हुई मंत्रो से शांतिधारा, पूजन में चढ़ाए अर्घ्य। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि आचार्य श्री चैत्य सागर महाराज एवं मुनिश्री अनुमान सागर महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठ्याचर्य पंडित डॉ आनंद प्रकाश शास्त्री के मार्ग दर्शन में जैन समाज के लोगो ने मंत्रोच्चार के कलशों से भगवान जिनेंद्र जयकारों के साथ अभिषेक किया। आचार्य श्री ने मंत्रो से बृहद शांतिधारा श्रीजी ने की। दशलक्षण महामंडल पूजन में उत्तम संयम धर्म की पूजन जैन समाज की महिला पुरुष और बालिकाओं ने संगीतमय भक्ति नृत्य के साथ अष्ट द्रव्य से पूजन अर्चना कर महा अर्घ्य समर्पित भगवान जिनेंद्र के समक्ष किए। ग्वालियर के 80 जैन मंदिरों में सुगंध दशमी मंदिर सज्जेगे ओर धूप अर्पित की। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि पर्युषण पर्व के छठवें दिन



सुगंध दशमी पर उत्तम संयम पर ग्वालियर शहर के 80 जैन मंदिर सज्जे। जैन समाज के लोग हर जैन मंदिर में पहुंचकर भगवान जिनेंद्र के चरणों में नमन करते हुए सुगंधित धूप अर्पित की। उत्तम संयम का मार्ग सबसे कठिन होता है। बिना संयम का मनुष्य पशु के समान है-आचार्य श्री आचार्य श्री सुबल सागर महाराज ने उत्तम सत्य पर धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक त्याग संयम को अपना आदर्श नहीं बनाओगे एवं अपनी लाईफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं करोगे तब तक आप मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते। उत्तम संयम का मार्ग सबसे कठिन होता है। बिना संयम का मनुष्य पशु के समान है जीवन में मनुष्य ही संयम ले सकता है देवों में भी संयम नहीं मिलता संयम के बिना मनुष्य की गाड़ी बिना ब्रेक वाली गाड़ी होती है बिना संयम धर्म के खाली खोखे होता है इस प्रकार मनुष्य का जीवन 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। संयम ही जीवन का श्रृंगार है।

प्रभारी मंत्री सिलावट ने की जल संसाधन विभाग की समीक्षा

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

ग्वालियर। जल संसाधन एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने सोमवार को व्हीआईपी सर्किट हाउस में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में सिंचाई व्यवस्था और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बांधों में उपलब्ध जल की स्थिति की जानकारी ली तथा खरीफ और रबी फसलों के लिए सिंचाई व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम में लगभग 48 हजार हेक्टेयर और रबी मौसम में लगभग 1 लाख 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधनों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। जल की स्थिति की सतत निगरानी करने तथा आवश्यकता के अनुसार सिंचाई व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

‘सेवा संकल्प अभियान’ में युवाओं ने लिया नशामुक्त जीवन का सामूहिक संकल्प

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित ‘माय भारत’ भोपाल द्वारा ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना समारोह का प्रमुख उद्देश्य रहा। यह आयोजन भोपाल के शासकीय नवीन महाविद्यालय की एमएसडब्ल्यू कक्षाओं-जन अभियान परिषद, रविशंकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शासकीय यूथ हॉस्टल टी.टी. नगर, सीआरसी हॉकी स्टेडियम तथा मनोहर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बैरिसिया सहित विभिन्न प्रमुख स्थलों पर किया गया। इन आयोजनों में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वयं नशे से दूर रहने और समाज को भी नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। समारोह के अंतर्गत युवाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व और नशामुक्ति के प्रति चेतना जागृत करने के



लिए विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं। आयोजन स्थलों पर हुए ‘संकल्प हस्ताक्षर अभियान’ में युवाओं ने व्यसनमुक्त जीवन अपनाने का संकल्प व्यक्त करते हुए अपने हस्ताक्षर किए। नशामुक्त भारत की अवधारणा पर केंद्रित नारा लेखन और ‘संकल्प चक्र’ जैसी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। इन गतिविधियों ने नशे के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का प्रभावी संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित युवाओं और नागरिकों को ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ की सामूहिक शपथ दिलाई गई। प्रतिभागियों ने किसी भी प्रकार के नशीले अथवा मादक पदार्थ का सेवन नहीं करने तथा अपने परिवार, मित्रों और परिचितों को भी नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने की प्रतिज्ञा ली। इस अवसर पर यह संदेश प्रमुखता से दिया गया कि स्वस्थ, जागरूक, अनुशासित और सशक्त युवा शक्ति ही विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर साकार कर सकती है। नशामुक्त युवा न केवल स्वयं का भविष्य सुरक्षित करते हैं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वन अधिकार पट्टे ने बदली रूपबसंत की जिंदगी

साहूकारों पर निर्भरता हुई खत्म, खेती से बढ़ी आय और परिवार का जीवन स्तर हुआ बेहतर

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

रायसेन जिले की जनपद पंचायत सांची अंतर्गत ग्राम पंचायत रतनपुर निवासी रूपबसंत आदिवासी पिता श्री रतनलाल आदिवासी के परिवार के लिए वन अधिकार योजना जीवन में बदलाव का माध्यम बनी है। वर्षों से जिस भूमि पर उनका परिवार खेती और मेहनत-मजदूरी कर जीवन-यापन करता था, उस भूमि का वन अधिकार पट्टा मिलने के बाद परिवार को न केवल भूमि पर अधिकार मिला, बल्कि विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने का रास्ता भी खुला। रूपबसंत बताते हैं कि उनके पिता वर्ष 1965 से ग्राम रतनपुर में निवास करते हुए

कब्जे की भूमि पर खेती करने के साथ मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। मिट्टी की दीवारों और कवेलू की छत वाले कच्चे मकान में परिवार रहता था। बारिश के दिनों में छत पर पानी डालकर रहना पड़ता था। विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ीं तो रूपबसंत और उनकी पत्नी भी खेती के साथ मेहनत-मजदूरी करने लगे। भूमि पर अधिकृत स्वामित्व का पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें शासकीय योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक सहित अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए उन्हें साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। भूमि का



पट्टा नहीं होने के कारण बैंक से कृषि ऋण प्राप्त

करना भी मुश्किल था। सिंचाई के लिए अपना बोर नहीं होने से दूसरे किसानों से पानी लेना पड़ता था और फसल आने पर उसके बदले राशि देनी पड़ती थी परिवार की अन्य जरूरतों, बच्चों की स्कूल फीस, कपड़े और त्योहारों के खर्च के लिए भी साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। फसल आने पर ब्याज सहित कर्ज चुकाने के बाद परिवार के पास बहुत कम राशि बचती थी। खेती होने के बावजूद रूपबसंत और उनके परिवार को घरेलू जरूरतों के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता था। रूपबसंत ने वर्ष 2019-20 में गांव जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित एमपी वनमित्र पोर्टल की जानकारी मिलने पर जनजातीय कार्य विभाग के

कार्यालय पहुंचकर ऑनलाइन आवेदन किया। पात्रता परीक्षण के बाद वर्ष 2020-21 में उन्हें 0.325200 हेक्टेयर कृषि भूमि का वन अधिकार पट्टा जारी किया गया। रूपबसंत कहते हैं कि पट्टा मिलने की खुशी उनके और परिवार के लिए अविस्मरणीय थी। वे कहते हैं, ‘पट्टा मिलने के बाद मुझे लगा कि अब मैं भी मजदूर से कृषक बन गया हूँ। अपनी भूमि पर अधिकार मिलने से हमारे परिवार में नई उम्मीद आई।’ भूमि का पट्टा मिलने के बाद रूपबसंत ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया। इसके माध्यम से उन्हें खेती के लिए बीज, खाद सहित अन्य कृषि आवश्यकताओं हेतु कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा मिली।

संपादकीय राहुल गांधी की गूंज कहां तक

देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों जातिगत जनगणना के मुद्दे से आगे बढ़कर देश की युवा तरुणाई तक पहुंच बनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल है-छात्रों और युवाओं के बीच उठाई जा रही उनकी यह गूंज आखिर कितनी दूर तक जाएगी? राहुल गांधी लंबे समय से जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़कर उठाते रहे हैं। लेकिन बिहार के चुनावी अनुभव ने इस रणनीति की राजनीतिक उपयोगिता पर सवाल खड़े किए। अब उन्होंने छात्रों और युवाओं की ओर रुख किया है। कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे के बाद 19 सितंबर को इंदौर में छात्रों की गूंज का पांचवां कार्यक्रम हुआ।

शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और सिस्टम राहुल गांधी के नए अभियान के प्रमुख विषय हैं। इन सवालों से असहमति की गुंजाइश कम है। देश का युवा सचमुच इन समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन यहीं राहुल गांधी के सामने असली सवाल खड़ा होता है-समस्या सबको दिखाई दे रही है, समाधान क्या है? जिस सिस्टम पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, वह एक दिन में बना हुआ ढांचा नहीं है। कांग्रेस सहित विभिन्न दलों की सरकारें दशकों तक इसे चलाती रही हैं। इसलिए अगर राोजगार गांधी इसे बदलने की बात करते हैं तो देश यह जानना चाहेगा कि वे सत्ता में आने पर इसे बदलेंगे कैसे?

करोड़ों युवाओं को केवल सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है। रोजगार का रास्ता सरकारी क्षेत्र के साथ निजी उद्योग, छोटे-मझोले उद्यम, स्टार्टअप, स्वरोजगार, कृषि और नई अर्थव्यवस्था से होकर भी गुजरता है। ऐसे में राहुल गांधी की आर्थिक नीति और रोजगार का वैकल्पिक मॉडल क्या होगा-यह सवाल उनके भाषणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

यहीं राहुल गांधी की राजनीति की एक बड़ी कमजोरी सामने आती है। वे कई बार भाजपा सरकारों की वास्तविक कमजोरियों को पकड़ने के बजाय नरेन्द्र मोदी सरीखी विशाल राजनीतिक मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनके हाथ से बार-बार फिसल जाती है।

सत्ता की अकुलाहट में कांग्रेस ने अपने कई

प्रभावी राजनीतिक अस्त्रों की धार भी कुंद की है। मोदी सरकार की नीतियों, प्रशासनिक विफलताओं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्थागत पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर लगातार और ठोस अभियान चलाने के बजाय बहस कई बार व्यक्ति-केन्द्रित हो जाती है।

दूसरी ओर भाजपा, कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप वाले राजनीतिक नैरेटिव पर घेरती है। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि इस आरोप का जवाब देते हुए उसे अपनी अल्पसंख्यक नीति और व्यापक सामाजिक न्याय की नीति को अधिक स्पष्ट करना होगा। कांग्रेस की पुरानी राजनीति को उसके आलोचक एक ऐसे सामाजिक समीकरण से जोड़ते रहे हैं जिसमें मुस्लिम मतदाताओं को उसका अपेक्षाकृत स्थिर आधार माना गया। यही धारणा अब कांग्रेस के लिए राजनीतिक बोझ भी बनती दिखाई देती है।

मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन भी कोई स्थायी या एकमुश्त राजनीतिक संपत्ति नहीं है। अलग-अलग राज्यों में जब उन्हें प्रभावी क्षेत्रीय विकल्प दिखाई देता है, तो उनका समर्थन उन दलों की ओर जाता रहा है। बिहार के चुनावी अध्ययन में भी मुस्लिम और यादव मतदाताओं के एक बड़े हिस्से के महागठबंधन की ओर जाने का उल्लेख मिलता है, जबकि दलित मतदाताओं के व्यवहार में चरण और क्षेत्र के अनुसार बदलाव दिखाई दिया।

यही बात कांग्रेस के व्यापक सामाजिक आधार पर भी लागू होती है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और स्वर्ण मतदाताओं का समर्थन भी किसी एक दल के लिए स्थायी नहीं है। चुनाव-दर-चुनाव समीकरण बदलते रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वह इन समुदायों को केवल चुनावी गणित का हिस्सा मानने के बजाय उनके लिए शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसरों के ठोस कार्यक्रम सामने रखे। राहुल गांधी के सामने चुनौती केवल भीड़ जुटाने की नहीं है। युवा एकरूप मतदाता नहीं है। किसी के लिए सरकारी नौकरी महत्वपूर्ण है, किसी के लिए निजी रोजगार, किसी के लिए उद्यमिता और किसी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

अब इटली से उठी बुरका-हिजाब प्रतिबंध की आवाज !

डॉ. मयंक चतुर्वेदी



इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के अनुसार, सच्चे एकीकरण का मतलब यह है कि प्रवासी देश की भाषा सीखें और वहां के सामाजिक ताने-बाने का सम्मान करें। बुरके को एक ऐसे सांस्कृतिक अलगाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो किसी समुदाय को मुख्यधारा के समाज में शामिल होने से रोकता है। यूरोप के देश फ्रांस में 'लाइसीते' (कट्टर धर्मनिरपेक्षता) का सिद्धांत लागू है



इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा देश के स्कूलों में बुरका-हिजाब पर प्रतिबंध लगाने और हर कक्षा में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने की घोषणा ने एक बार फिर वैश्विक पटल पर बुरका-हिजाब ला दिया है। वस्तुतः विश्व के कई देशों की सरकारों ने यह पाया है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक पहचान के बीच इस्लाम से जुड़ी ये दो आदत आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था जैसे हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सरकारी बैंक और संवेदनशील इमारतें सीसीटीवी और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (चेहरा पहचानने वाली तकनीक) पर भारी पड़ रही हैं।

बुरका और हिजाब से चेहरा पूरी तरह ढक जाने के कारण किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करना असंभव हो जाता है। श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों ने पाया है कि चरमपंथी और आत्मघाती हमलावर अपनी पहचान छिपाने और हथियारों की तस्करी के लिए बुरके का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण सुरक्षा के लिहाज से कानून प्रवर्तन एजेंसियां सार्वजनिक स्थानों पर हर नागरिक का चेहरा खुला रखना अनिवार्य मानती हैं।

इसके अलावा, पश्चिमी देश, विशेषकर यूरोपीय राष्ट्र, एक बहुसांस्कृतिक समाज में प्रवासियों के पूरी तरह घुलने-मिलने पर जोर देते हैं। वैसे भी ईसानी बातचीत और सामाजिक जुड़ाव में चेहरे के हाव-भाव सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। चेहरा ढके होने से बातचीत में एक अघोषित दीवार खड़ी हो जाती है, जो प्रवासियों को स्थानीय नागरिकों से अलग करती है।

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के अनुसार, सच्चे एकीकरण का मतलब यह है कि प्रवासी देश की भाषा सीखें और वहां के सामाजिक ताने-बाने का सम्मान करें। बुरके को एक ऐसे सांस्कृतिक अलगाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो किसी समुदाय को मुख्यधारा के समाज में शामिल होने से रोकता है।

यूरोप के देश फ्रांस में 'लाइसीते' (कट्टर धर्मनिरपेक्षता) का सिद्धांत लागू है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के प्रमुख धार्मिक प्रतीकों (चाहे वह बड़ा ईसाई क्रॉस हो, यहूदी टोपी हो, या मुस्लिम हिजाब/बुरका हो) के प्रदर्शन पर रोक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक क्षेत्र पूरी तरह से तटस्थ रहे। साथ ही, उदारवादी और नारीवादी विचारकों का एक बड़ा वर्ग बुरके और नकाब को पितृसत्तात्मक दमन का प्रतीक मानता है। सरकार का तर्क है कि बहुत सी युवा लड़कियों और महिलाओं को उनके परिवारों या मजहबी संरक्षकों द्वारा अपनी इच्छा के विरुद्ध चेहरा ढकने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए प्रतिबंध लगाने वाले देशों का मानना ​​है कि यह कानून उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है जो अपनी मर्जी से इसे नहीं पहनना चाहतीं। फ्रांस साल 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुरका

डा. जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित हो रहे राष्ट्रीय और वैश्विक विश्लेषणों में कहा जा रहा है कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भारत के लिए बहुआयामी आर्थिक उपयोगिताएं मिली हैं। इस ऐतिहासिक सम्मेलन ने न केवल भारत की साख को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत के आर्थिक विकास का एक सुदृढ़ और विस्तृत खाका भी तैयार किया है। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत ने दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के सामने अपनी आर्थिक स्थिरता, नीतिगत निरंतरता और बाजार की असीम क्षमताओं का प्रभावी प्रदर्शन किया है। सम्मेलन ने भारतीय बाजार के लिए बहुराष्ट्रीय व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) के पुनर्गठन तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के क्षेत्र में असीम संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। इस 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि भारत अब वैश्विक आर्थिक नीतियों और वित्तीय संरचना के निर्धारण में एक निर्णायक नीति-निर्माता तथा ग्लोबल साउथ की सशक्त और भरोसेमंद आवाज बनकर उभरा है। सम्मेलन के दौरान वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के लोकतांत्रीकरण पर विशेष बल दिया गया, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमरीकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने और सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं (लोकल करेंसीज) में द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर ऐतिहासिक सहमति बनी। स्थानीय मुद्रा में आयात-निर्यात के लेन-देन से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुस्तरीय आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे।

इससे न केवल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बना रहने वाला अनावश्यक दबाव काफी हद तक कम होगा, बल्कि वैश्विक बाजार में मुद्रा विनिमय (करंसी कन्वर्जन) के दौरान होने वाली अतिरिक्त वित्तीय लागत में भारी बचत होगी। परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुएं और सेवाएं अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी (कॉस्ट कंपैटिटिव) बन सकेंगी, जिससे देश के कुल निर्यात में क्रांतिकारी उछाल आने की पूरी संभावना है। आर्थिक मोर्चे पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों की ब्रिक्स के साझेदार देशों- ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका तथा नए शामिल हुए सदस्य देशों से आने वाले पूंजीगत निवेश और उच्च तकनीक से अभूतपूर्व संबल प्राप्त होने का रहा है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापारिक नियमों, सीमा शुल्क (कस्टम्स ड्यूटीज) की प्रक्रियाओं और विनियामक अनुपालनों में सरलीकरण लाने पर बनी सहमति से भारत में मैयुफैक्चरिंग, भारी उद्योग, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में एक क्रांति का सूत्रपात होगा। वैश्विक कंपनियों द्वारा अपनी

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सप्लाई चेन को अधिक विविध और विश्वसनीय बनाया है। इसी मजबूती और लचीलेपन के कारण भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी दुनिया को विकास और स्थिरता का भरोसा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही। भारत के यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट्स और ओपन इकोसिस्टम ने वित्तीय समावेशन और रियल-टाइम ट्रांजैक्शन को नई गति दी है, जिसे आज दुनिया के कई देश अपना रहे हैं। साथ ही, भारत राजनीतिक स्थिरता, पूर्वानुमानित नीतियों और व्यापार-अनुकूल सुधारों की बदौलत दुनिया की सबसे खुली और निवेश-अनुकूल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है।



आपूर्ति श्रृंखला को विविधता देने और भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की रणनीति से देश में न केवल नए औद्योगिक गलियारों का निर्माण होगा, बल्कि बुनियादी ढांचे का भी अभूतपूर्व कायाकल्प होगा। इसके अतिरिक्त भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और ई-गवर्नेंस मॉडल्स के सफल प्रयोगों से दुनिया भर में जो धाक जमाई है, उसे अब ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों और अफ्रीकी व एशियाई महाद्वीपों की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे भारत का टेक-निर्यात बढ़ेगा और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक पहचान और नई वित्तीय ताकत प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच भी चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 7.8 प्रतिशत की आश्चर्यजनक और मजबूत जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। यह साबित करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी का

प्रभाव न्यूनतम रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां एक ओर दुनिया भर में व्यापार की बाधाएं बढ़ रही हैं, वहीं भारत विभिन्न देशों के बीच इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि 2014 से लेकर अब तक भारत ने लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सप्लाई चेन को अधिक विविध और विश्वसनीय बनाया है। इसी मजबूती और लचीलेपन के कारण भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी दुनिया को विकास और स्थिरता का भरोसा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही। भारत के यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट्स और ओपन इकोसिस्टम ने वित्तीय समावेशन और रियल-टाइम ट्रांजैक्शन को नई गति दी है, जिसे आज दुनिया के कई देश अपना रहे हैं। साथ ही, भारत राजनीतिक स्थिरता, पूर्वानुमानित नीतियों और व्यापार-अनुकूल सुधारों की बदौलत दुनिया की सबसे खुली और निवेश-अनुकूल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। निःसंदेह पूरी दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था की अहमियत को स्वीकार

किया जा रहा है। देश की इस सुदृढ़ स्थिति को स्वीकार करते हुए हाल ही में प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जापानी क्रेडिट रेटिंग ने भारत की सॉवरैन रेटिंग को बीबीबी प्लस से बढ़ाकर ए माइन्स की उत्कृष्ट श्रेणी में अपग्रेड कर दिया है। रेटिंग में किया गया यह सुधार भारत की मजबूत आंतरिक खपत मांग, सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे बुनियादी ढांचागत पूंजीगत व्यय (पब्लिक कैपेक्स) और देश की सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के अटूट विश्वास पर एक मजबूत मुहर लगाता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि 11 सितंबर तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 780.78 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार की यह वित्तीय ढाल भारत को वैश्विक वित्तीय झटकों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार के उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली अचानक वृद्धि से पूर्ण सुरक्षा और संप्रभुता प्रदान करती है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए सख्त राजकोषीय अनुशासन के कारण देश का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के सुरक्षित स्तर पर आ गया है। निश्चित रूप से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए आर्थिक और कारोबारी दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है।

ब्रिक्स सम्मेलन से उत्पन्न हुए इन अभूतपूर्व अवसरों का शत-प्रतिशत लाभ उठाने और अर्थव्यवस्था को निरंतर 7.8 प्रतिशत से अधिक की तीव्र विकास दर पर बनाए रखने के लिए भारत को अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताओं पर तीन तरह से पूरी तत्परता से काम करना होगा। पहला, ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर स्थानीय मुद्रा व्यापार के निष्पादन के लिए एक पारदर्शी और कुशल क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म की स्थापना करनी होगी ताकि व्यापारियों को विनिमय दर के जोखिमों से बचाया जा सके। दूसरा, भविष्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे अति आधुनिक क्षेत्रों (डीप-टेक) में अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने होंगे। तीसरा, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को आधुनिक तकनीक, सस्ता संस्थापत ऋण और वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना होगा।

ई-स्कूटी ने घटाई कॉलेज की दूरी, सपनों को दी नई रफ्तार

जिले के 132 स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को मिला मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

मेहनत से मिली सफलता जब जीवन में आगे बढ़ने का साधन भी बन जाए, तो वह पुरस्कार वास्तविक बदलाव का माध्यम बन जाता है। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल, भोपाल की मेधावी छात्रा मुस्कान सनोधिया के लिए मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत मिली ई-स्कूटी ऐसी ही सौगात है। यह उनके लिए केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के सपनों को साकार करने का विश्वास और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा भोपाल जिले के 132 स्कूलों के

मेधावी छात्र-छात्राओं को विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ई-स्कूटी प्रदान की गई। योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों में मुस्कान सनोधिया के साथ अनुराग तिवारी, गरिमा श्रीवास, रागिनी अहिरवार, मिलमा खान, साम्या, रानी सपले और देवेश गुप्ता सहित अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी शामिल हैं। कॉलेज की पढ़ाई के लिए प्रतिदिन आने-जाने में विद्यार्थियों का काफी समय व्यतीत होता था। आवागमन की असुविधा के कारण कई बार समय पर कॉलेज पहुंचना भी चुनौती बन जाता था। ई-स्कूटी मिलने से अब उनकी यह चिंता काफी हद तक दूर हो गई है। विद्यार्थी समय पर कॉलेज पहुंच सकेंगे, नियमित

रूप से कक्षाओं में शामिल हो सकेंगे और आवागमन में बचने वाले समय का उपयोग पढ़ाई तथा भविष्य की तैयारियों में कर पाएंगे। मुस्कान सनोधिया ने बताया कि ई-स्कूटी मिलने से कॉलेज तक पहुंचना अधिक सहज होगा। प्रतिदिन आवागमन में लगने वाले समय की बचत होगी और पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। यह सुविधा उन्हें अधिक नियमितता और एकाग्रता के साथ अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करेगी। अन्य लाभान्वित विद्यार्थियों ने भी ई-स्कूटी को अपने शैक्षणिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली सौगात बताया। उनका कहना है कि



स्वयं का आवागमन साधन मिलने से दूसरों पर निर्भरता कम होगी और वे पढ़ाई सहित अन्य आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना विद्यार्थियों को केवल कॉलेज तक पहुंचने की

सुविधा ही नहीं दे रही, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित कर रही है। ई-स्कूटी के रूप में मिली यह सहायता मेधावी विद्यार्थियों को भरोसा दिलाती है कि उनकी मेहनत को सम्मान मिल रहा है

और उच्च शिक्षा की राह में सरकार उनके साथ खड़ी है। मुस्कान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल उनके जैसे विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा जारी रखने में अत्यंत मददगार है। उन्होंने इस सुविधा का पूरी जिम्मेदारी के साथ उपयोग करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने बेहतर भविष्य के निर्माण का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का प्रभाव केवल ई-स्कूटी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। मेधावी छात्र-छात्राओं को उनकी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए

सम्मानित होते देखकर अन्य विद्यार्थी भी नियमित अध्ययन, अनुशासन और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए हैं। इससे विद्यालयों में स्वस्थ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना है। विद्यार्थियों का यह विश्वास भी मजबूत हुआ है कि उनकी प्रतिभा और परिश्रम को सरकार पहचानती है तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना ने शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अब वे बड़े लक्ष्य निर्धारित कर अधिक मेहनत के साथ पढ़ाई करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

25 सितंबर को भोपाल में होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का भव्य शुभारंभ

संभाग आयुक्त शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की तैयारियों को समीक्षा

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा एवं पीएम ई-बस सेवा का भव्य शुभारंभ 25 सितंबर 2026 को भोपाल के भेल दशहरा मैदान से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 300 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इनमें पीएम ई-बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा दोनों श्रेणी की बसें शामिल होंगी। संभाग आयुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों को समीक्षा की ओर समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त डॉ. किनोद यादव, उपायुक्त राजस्व श्रीमती भारती देवी मिश्रा, संभाग के सभी जिलों के अपर कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।



कार्यक्रम स्थल तक नागरिकों को आने जाने के लिए रूट और बसों की संख्या निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक रूट के लिए एक रूट प्रभारी तथा दो बस प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। बसों के प्रस्थान स्थल और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग

को पहले से निर्धारित करने के साथ बसों की तकनीकी जांच और फिटनेस भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यात्रियों के लिए भोजन, नाश्ता और पेयजल की व्यवस्था के साथ बसों में पानी एवं प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध

करने को कहा गया है। गणेश विसर्जन के चलते विशेष यातायात व्यवस्था 25 सितंबर को गणेश विसर्जन के कार्यक्रम भी होने के कारण यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बसों के मार्गों पर भीड़ वाले

स्थानों की पहले से पहचान करने तथा यातायात को सुगम बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम गठित कर उसे संभाग स्तर पर गठित कंट्रोल रूम के साथ समन्वय करने को कहा गया है। सभी नोडल अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पार्किंग और यातायात की जिम्मेदारी पुलिस विभाग को कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ पहुंच मार्गों पर चल रहे सड़क निर्माण एवं मेट्रो कार्य को देखते हुए वैकल्पिक और सुगम रूट निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिलों से आने वाली बसों के आवागमन को सुचारु रखने और जाम की स्थिति पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। गणेश विसर्जन के जुलूसों को देखते हुए ग्रामीण पुलिस और भोपाल नगरीय पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय बैरसिया में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया

■ एक सत बुलेटिन, बैरसिया।

स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय बैरसिया में 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत 'मेरा सेवा संकल्प-मेरा योगदान' विषय पर चित्रकला एवं भाषण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा समाज के प्रति सकारात्मक योगदान की भावना विकसित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ इसके पश्चात विद्यार्थियों ने 'मेरा सेवा संकल्प-मेरा योगदान' विषय पर चित्रकला के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया वहीं भाषण कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सेवा भावना, सामाजिक जिम्मेदारी तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों पर



विचार व्यक्त किए इस अवसर पर डॉ. शोएब खान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सेवा भावना एवं सामाजिक दायित्व के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समाजहित में सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजू तिलैथे ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि

सेवा केवल किसी एक कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना भी सेवा का महत्वपूर्ण स्वरूप है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जीवन में सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रो. शारदा सिंह ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन डॉ. उमेश कुल्हारे ने किया।

‘रेडियो से कराओके तक’ में गूँजे पुराने दौर के सदाबहार गीत

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

20 सितंबर 2026 को नीलकंठ संगीत ग्रुप भोपाल द्वारा 'रेडियो से कराओके तक' संगीत संध्या का आयोजन चाइना टेरेस, कोलार रोड, भोपाल में शानदार तरीके से किया गया। कार्यक्रम में पुराने रेडियो युग की मधुर यादों को संगीत के माध्यम से फिर से जीवंत किया गया। कार्यक्रम में गायकों ने एक से बढ़कर एक सदाबहार गीतों की शानदार प्रस्तुतियाँ दीं। भोपाल के साथ-साथ जबलपुर से भी कई गायकों ने कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी प्रस्तुतियों से सभां बांधा। इस सफल आयोजन के पीछे आयोजक मनराज एवं वंदना की जोड़ी की मेहनत और समर्पण विशेष रूप से देखने को मिला। दोनों ने मिलकर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और कलाकारों के समन्वय को बेहतरीन तरीके से संभाला।



कार्यक्रम में मिलन आर्टिस्ट की जोरदार एंकरिंग ने भी खूब रंग जमाया। उनकी शानदार प्रस्तुति और मंच संचालन ने पूरे कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। इस अवसर पर अमित शर्मा जी को

‘भजन गायन गौरव सम्मान’ से सम्मानित किया गया। वहीं श्री A. K. Srivastava, IFS (Retd.) को ‘विशिष्ट व्यक्तित्व गौरव सम्मान’ से सम्मानित किया गया। संगीत प्रेमियों से खचाखच भरे

कार्यक्रम में पुराने गीतों की मधुर धुनों ने सभी को पुराने रेडियो युग की यादों में पहुंचा दिया। नीलकंठ संगीत ग्रुप भोपाल का यह आयोजन संगीत, सम्मान और मनोरंजन का खूबसूरत संगम बनकर यादगार रहा।

प्रमुख पर्वों के दौरान भोपाल मंडल से होकर 12 विशेष ट्रेन सेवाओं का संचालन

दीपावली एवं छठ पूजा पर्व पर यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा जैसे प्रमुख पर्वों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं अतिरिक्त यात्री मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न दिशाओं में विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल मंडल से होकर 06 जोड़ी अर्थात कुल 12 विशेष ट्रेन सेवाएं संचालित की जाएंगी। इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच यात्रियों को अतिरिक्त रेल परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। 1. रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति पितृपक्ष/पर्व विशेष ट्रेन गाड़ी संख्या 01661/01662 रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति विशेष ट्रेन के 03-03 फेरे निर्धारित किए गए हैं। गाड़ी संख्या

01661 रानी कमलापति से 27 सितम्बर, 02 एवं 07 अक्टूबर 2026 को तथा वापसी में गाड़ी संख्या 01662 गया से 30 सितम्बर, 05 एवं 10 अक्टूबर 2026 को चलेगी। यह विशेष ट्रेन भोपाल मंडल के नर्मदापुरम, इटारसी एवं पिपरिया सहित मार्ग के प्रमुख स्टेशनों से होकर संचालित होगी। आगे यह नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन एवं अनुराह नारायण रोड होकर गया पहुंचेगी। 2. रानी कमलापति-रीवा-रानी कमलापति पर्व विशेष ट्रेन गाड़ी संख्या 02191/02192 रानी कमलापति-रीवा-रानी कमलापति विशेष ट्रेन के 04-04 फेरे चलाए जाएंगे। गाड़ी संख्या 02191 रानी कमलापति से 17 एवं 24 अक्टूबर तथा 07 एवं



14 नवम्बर 2026 को तथा वापसी में गाड़ी संख्या 02192 रीवा से निर्धारित तिथियों के अनुसार संचालित होगी। यह विशेष ट्रेन विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, मैहर एवं सतना स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए रीवा पहुंचेगी। 3. रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा पूजा विशेष ट्रेन गाड़ी संख्या 01710/01709 रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा विशेष ट्रेन के 06-06 फेरे अर्थात कुल

12 सेवाएं संचालित की जाएंगी। गाड़ी संख्या 01710 रीवा से 10 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2026 तक तथा वापसी में गाड़ी संख्या 01709 डॉ. अंबेडकर नगर से 11 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2026 तक निर्धारित तिथियों पर चलेगी। यह ट्रेन टर्मिनस-सुल्तानपुर विशेष ट्रेन गाड़ी संख्या 04212/04211 सुल्तानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सुल्तानपुर विशेष ट्रेन के 04-04 फेरे चलाए जाएंगे। गाड़ी संख्या 04212 सुल्तानपुर से 21 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2026 तक तथा वापसी में गाड़ी संख्या 04211 लोकमान्य तिलक

टर्मिनस से 22 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2026 तक निर्धारित तिथियों पर चलेगी। भोपाल मंडल में यह ट्रेन बीना, रानी कमलापति एवं इटारसी स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए आगे खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण एवं ठाणे होकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। 5. वाराणसी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-वाराणसी विशेष ट्रेन गाड़ी संख्या 04226/04225 वाराणसी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-वाराणसी विशेष ट्रेन के 04-04 फेरे चलाए जाएंगे। गाड़ी संख्या 04226 वाराणसी से 22 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2026 तक तथा वापसी में गाड़ी संख्या 04225 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 23 अक्टूबर से 13 नवम्बर 2026 तक निर्धारित तिथियों पर चलेगी। खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण एवं ठाणे होकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

संक्षिप्त

समाचार

एनएसई आईपीओ जीएमपी 310 रुपये सेघटकर 61 रुपये के स्तर पर आया

नईदिल्ली, एजेंसी। एनएसई के आईपीओ के जीएमपी में भारी गिरावट देखने को मिली है। इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में



एनएसई का आईपीओ आज 61 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 3.42 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। इससे पहले 18 सितंबर को आईपीओ 111 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले 17 सितंबर को आईपीओ का जीएमपी 142 रुपये पर था। बता दें, एक वक्त पर एनएसई के आईपीओ का जीएमपी 310 रुपये था। यानी वहां से घटकर अब 61 रुपये के स्तर पर आ गया। एनएसई के आईपीओ को दिन में पुरा भर गया है। आईपीओ को दो दिन में 1.04 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 0.69 गुना, वयुआईबी में 1.32 गुना और एनआईआई में 1.46 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। बता दें, आईपीओ 17 सितंबर को खुला था। निवेशकों के पास 21 सितंबर यानी कल तक दांव लगाने का मौका रहेगा। एकर निवेशकों के लिए यह इश्यू 16 सितंबर तक खुला था। कंपनी ने एकर निवेशकों से 6746.18 करोड़ रुपये जुटाए थे। एनएसई के आईपीओ का साइज 30,000 करोड़ रुपये से घटाकर 22561.57 रुपये कर दिया गया है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। आईपीओ के जरिए सिर्फ मौजूदा निवेशकों की तरफ से बिक्री हो रही है। एनएसई के आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 1700 रुपये से 1785 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 8 शेयरों का बनाया गया है। किसी भी निवेशक को कम से कम 14280 रुपये का दांव लगाना होगा।

सोमवार को बंद रहेंगे बैंक

नईदिल्ली, एजेंसी। सोमवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 21 सितंबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैलेंडर के मुताबिक कल सोमवार को बैंक कुछ राज्यों में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये कल किन राज्यों में और वयों बैंक बंद रहने वाले हैं। कल सोमवार 21 सितंबर को बैंक असम और केरल में बंद रहेंगे। असम में बैंक श्रीमंत शंकरदेव जन्मोत्सव और केरल में बैंक श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के कारण बैंक नहीं खुलेंगे। यहां सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहेंगे। असम और केरल के अलावा बैंक देश के बाकी सभी राज्यों में खुले रहेंगे। श्रीमंत शंकरदेव जन्मोत्सव मुख्य रूप से असम में मनाया जाता है। यह महान संत, कवि, समाज सुधारक और वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की जयंती है। माना जाता है कि उनका जन्म 1449 में असम में हुआ था। उन्होंने असम में एकाशरण नामधर्म यानी भवित परंपरा को आगे बढ़ाया और समाज को धार्मिक-सामाजिक एकता का संदेश दिया। असम में शंकरदेव जन्मोत्सव 21 सितंबर को मनाया जाएगा। श्री नारायण गुरु समाधि दिवस मुख्य रूप से केरल के वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में मनाया जाता है। श्री नारायण गुरु एक आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उनका प्रसिद्ध संदेश था 'एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मनुष्य के लिए। शिवगिरी में उन्होंने समाधि प्राप्त की थी। इसी घटना की याद में समाधि दिवस मनाया जाता है। देश के बाकी राज्यों में खुली रहेंगे बैंक ब्रांच दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगाना जैसे तमाम राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।

350 की रफ्तार और सीधा जापान को टक्कर भारत बनाएगा ‘मेड इन इंडिया’ बुलेट ट्रेन

नई दिल्ली, एजेंसां। भारत अंब सिर्फ बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि हाई-स्पीड ट्रेन तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। रेलवे मंत्रालय की कैबिनेट प्रस्ताव संबंधी जानकारी के मुताबिक भारत 2030 तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड वाली स्वदेशी हाई-स्पीड ट्रेन बी35 विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। यह जापान की अगली पीढ़ी की 10 सीरीज की ट्रेनों के बराबर डिजाइन स्पीड होगी।

अभी भारत में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की संशोधित लागत अब 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। यह 2015 में तैयार किए गए शुरुआती अनुमान से करीब दोगुनी है। बड़ी हुई लागत में करीब 1 लाख करोड़ रुपये की राशि वजटीय सहायता से पूरी की जाएगी।

जापान की ई 5 की जगह आएगी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रेल मंत्रालय ने कैबिनेट को बताया है कि भारत ने ब्र85 ट्रेन विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जापान ने दिसंबर 2024 में भारत को बताया था कि मौजूदा ई 5 सीरीज की ट्रेन का उत्पादन धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है। जापान की योजना के मुताबिक ई 10 ट्रेनों का उत्पादन 2030



में शुरू होगा और इनके 2034 तक संचालन में आने की उम्मीद है। भारत जब तक ई 10 ट्रेनें हासिल करेगा, तब तक 350 की स्पीड वाली अपनी खुद की बी 35 स्वदेशी ट्रेन तैयार कर लेगा। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर पर ई 10 का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की शुरुआत 8 हाई-स्पीड ट्रेनों के साथ होगी। इन ट्रेनों की डिजाइन स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अधिकतम परिचालन गति 249 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी।

ट्रेन से रोज सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, 608 किमी ट्रैक पर लगेगा ‘कवच’, रेलवे का बड़ा सेफ्टी प्लान

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े इंग्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। रेलवे ने अलग-अलग जोन और डिवीजन में कवच 4.0,



इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रिक ट्रेवशन सिस्टम अपग्रेड और 4-लेन रोड ओवरब्रिज समेत कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ट्रेन संचालन को ज्यादा सुरक्षित बनाना, आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम को मजबूत करना और रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना है। कवच भारत में विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसका उद्देश्य ट्रेनों को टक्कर से बचाने और रेड सिग्नल पार करने जैसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना है। जरूरत पड़ने पर यह सिस्टम अपने आप ब्रेक लगाने में भी मदद कर सकता है। रेल मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन में 607.7 रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 252 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक, इससे डिवीजन के बचे हुए चिन्हित सेक्शनों में भी कवच सिस्टम की कवरज बढ़ेगी और ट्रेन संचालन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। रेलवे ने सेंट्रल रेलवे के सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाने को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 209 करोड़ रुपये है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कंप्यूटर आधारित सिग्नलिंग तकनीक है। यह रेलवे सिग्नल और ट्रैक के पॉइंट्स को नियंत्रित करने में मदद करती है, ताकि एक-दूसरे से टकराने वाले ट्रेन मूवमेंट को रोका जा सके। रेलवे के मुताबिक, आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम से डिवीजन में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आगे सिस्टम लागू करने में भी मदद मिलेगी। साउथ कोस्ट रेलवे के सावल्यापुरम-गुंटूर सेक्शन में इलेक्ट्रिक ट्रेवशन सिस्टम को 1×25 बग्घ से बढ़ाकर 2×25 बग्घ करने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। करीब 73 रूट किलोमीटर के इस सेक्शन पर परियोजना की लागत 142 करोड़ रुपये होगी। रेलवे के अनुसार यह प्रोजेक्ट कुल 146 ट्रैक किलोमीटर को कवर करेगा। ट्रेवशन सिस्टम की क्षमता बढ़ने से इस सेक्शन पर बढ़ते रेल संचालन को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी और इलेक्ट्रिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। रेलवे ने गुजरात में भी एक बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वेस्टर्न रेलवे के उधना-उकाई सोनगढ़ सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग नंबर 53 की जगह 4-लेन रोड ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 133.2295 करोड़ रुपये है। इसे राज्य सरकार के साथ लागत साझा करने के आधार पर लागू किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक, ऋक्षक बनने से लेवल क्रॉसिंग पर सड़क यातायात सुचारू होगा और सड़क एवं रेल त्रयायात के बीच होने वाला हस्तक्षेप कम होगा।

भारत कैसे बनेगा विकसित, सीईए अनंत नागेश्वरन ने कहा- प्राइवेट सेक्टर का पैसा जरूरी, राज्यों को बताए 3 बड़े काम

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी सजग नजर आ रही है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर के पैसे की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कहा जा रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने शनिवार को कहा कि भारत का वचत आधार मजबूत है और इसे आगे भी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन 2047 तक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी पूंजी से बड़े स्तर पर निवेश जुटाना जरूरी होगा। उन्होंने यह बात 'फाइनेंसिंग इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत' विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में कही।

उन्होंने कहा कि निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में जमीन, बिजली और लॉजिस्टिक्स जैसी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही प्रभावी सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी जरूरी है, ताकि निवेशकों को अलग-अलग मंजूरियों के लिए लंबी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।

सीईए अनंत नागेश्वरन ने सम्मेलन में कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित राज्यों पर निर्भर करता है। उन्होंने राज्यों के सामने आर्थिक प्रगति में तेजी लाने के लिए तीन मुख्य प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने कहा कि निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा। इसके लिए राज्यों में जमीन, बिजली और लॉजिस्टिक्स की

आसान उपलब्धता के साथ सिंगल-विंडो क्लियरेंस व्यवस्था को मजबूत बनाना। मजबूत प्रोजेक्ट-प्रिपेरेशन्स और प्रामाणिक रिपोर्ट तैयार करना ताकि थ्रेलू व बहुपक्षीय वित्तपोषण आसानी से मिल



सके। इसके साथ ही विकास की संभावनाओं वाले पिछड़े जिलों की तरफ क्रेडिट प्रवाह बढ़ाना। राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाना होगा। सीईए ने कहा कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद बुनियादी ढांचे पर खर्च को बढ़ाना जरूरी है। इस संदर्भ में उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव के उस प्रस्ताव का जिक्र किया, जिसमें वित्त वर्ष 2031-32 तक राज्यों के पूंजीगत परिव्यय को तत्क्षकक 2.4% से बढ़ाकर 3% करने

की बात कही गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नागेश्वरन ने भारत के सामने मौजूद दोहरी चुनौती को रेखांकित किया। एक तरफ देश को 2047 तक के दीर्घकालिक विकास लक्ष्य को बनाए रखना है,



वहीं अगले पांच वर्षों में संसाधन जुटाने की रफ्तार भी बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध वित्तीय अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत को निवेश और संसाधन जुटाने की क्षमता मजबूत करनी होगी। सम्मेलन में भारत के मैक्रोइकोनॉमिक आउटलुक, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्तपोषण और ऊर्जा संक्रमण के लिए फंडिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई।

रोबोकिड्ज एडुवेंचर्स के आईपीओ ने खुलने से पहले ही मचाया तहलका, 106 के शेयर पर 51 जीएमपी,लिस्टिंग पर 48% मुनाफे का संकेत

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीओ के लिए अगला हफ्ता काफी व्यस्त रहने वाला है। एसएमई सेगमेंट का एक आईपीओ खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में तहलका मचाए हुए है। इसका जीएमपी लिस्टिंग पर 48 फीसदी से ज्यादा गेन का संकेत दे रहा है। इस आईपीओ का नाम रोबोकिड्ज एडुवेंचर्स है। आईपीओ कल यानी सोमवार से निवेशकों के लिए खुलेगा। कंपनी का इश्यू साइज 31.09 करोड़ रुपये है, जो पूरी तरह फ्रेश होगा। इसमें निवेशक 23 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। इसका प्राइस बैंड 100 से 106 रुपये के बीच है। एक लॉट में 1,200 शेयर हैं। एक रिटेल निवेशक को कम से कम दो लॉट के लिए बोली लगानी होगी। इसके लिए 2,54,400 रुपये लगाने होंगे। इसकी लिस्टिंग 28 सितंबर को हो सकती है। एसएमई सेगमेंट का रोबोकिड्ज एजुवेंचर्स



51 रुपये था। आईपीओ का प्राइस अगर 106 रुपये प्रति शेयर माना जाए तो इसमें अभी से 48.11% की तेजी आ चुकी है। इस तेजी के साथ इसकी कीमत प्रति शेयर 157 रुपये हो चुकी है।

अगर मान लें कि लिस्टिंग तक इतनी ही तेजी रहती है तो यह निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा दे सकता है। हालांकि जीएमपी कोई फिक्स रिटर्न

आईपीओ ग्रे मार्केट में धूम मचाए हुए है। आज संडे को सुबह 10 बजे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम

आईपीओ ग्रे मार्केट में धूम मचाए हुए है। आज संडे को सुबह 10 बजे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम

आईपीओ ग्रे मार्केट में धूम मचाए हुए है। आज संडे को सुबह 10 बजे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम

कभी कॉलेज फीस भरनी थी मुश्किल, फिर ऐसी मुलाकात कि 6 लाख से बनी 75 करोड़ की कंपनी

नई दिल्ली, एजेंसी। किस्मत कहां ले जाए कोई नहीं जानता। मदुरे के प्रसन्ना वेंकटेश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कभी कॉलेज फीस भरने के लिए भी संघर्ष करने वाले प्रसन्ना की चेन्नई के एम. कुमारवेलन की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। साल 2010 में सिर्फ 6 लाख रुपये की पूंजी से दोनों ने मद्रास कॉफी हाउस की नींव रखी थी। आज इस ब्रांड के देशभर में करीब 180 आउटलेट्स हैं। मलेशिया और श्रीलंका में भी इसकी मौजूदगी है। यह ब्रांड रोजाना करीब 50,000 कप कॉफी बेचता है। इसका टर्नओवर 75 करोड़ रुपये है। 5 कर्मचारियों से शुरू हुई यह कंपनी आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। आइए, यहां प्रसन्ना वेंकटेश और एम. कुमारवेलन की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

ऐसे हुई दोनों की मुलाकात प्रसन्ना वेंकटेश का जन्म तमिलनाडु के मदुरे में एक साधारण परिवार में हुआ। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साथ या उड़ गया। परिवार चलाने के लिए उनकी मां और



बहनों को काम करना पड़ा। केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज फीस का इंतजाम करने के लिए उन्होंने दोस्तों के साथ एक छोटी कैटैनल शुरू की। यह भले असफल रही। लेकिन, इसने उन्हें उद्यमिता का पहला स्वाद चखा दिया। रियल एस्टेट और एलआईसी एजेंट जैसे कई काम करने के बाद 2008 में उनकी मुलाकात एस. संगीता रेस्तारं चैन चलाने वाले एम. कुमारवेलन से हुई। कुमारवेलन ने प्रसन्ना के व्यावसायिक जुनून को पहचानकर अपने

रेस्तारं में लाइम सोडा का स्टॉल लगाने का मौका दिया। हालांकि, वह स्टॉल ज्यादा नहीं चलता। लेकिन, दोनों के बीच भरोसे का मजबूत रिश्ता कायम हो गया।

दोनों संस्थापकों ने महसूस किया कि असली साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी सिर्फ बड़े रेस्तारं में उपलब्ध थी। वहीं, छोटे भोजनालय साधारण कॉफी ही परोसते थे। इस अंतर को भुनाने के लिए उन्होंने 2010 में चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में 'मद्रास कॉफी हाउस' का पहला आउटलेट

खोला। प्रसन्ना ने 2 लाख रुपये का कर्ज लिया। वहीं, कुमारवेलन ने अपना पैसा लगाया। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन का अनुभव रखने वाले कुमारवेलन और प्रसन्ना ने बिजनेस को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया। चेन्नई के पैरीज कॉर्नर में 2,500 वर्ग फीट का सेंट्रल स्टोर और हेड ऑफिस बनाया गया, जहां से सभी आउटलेट्स को सख्त गुणवत्ता मानकों के तहत कॉफी बीन्स की सप्लाई की जाती है। मद्रास कॉफी हाउस में आज फिल्टर कॉफी और कुकीज के अलावा 5 रुपये के कॉकटेल समोसे से लेकर चिल्ड्रन ड्रिंको तक 40-50 तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा आउटलेट चेन्नई एयरपोर्ट पर है। वहां रोजाना की बिक्री करीब 3 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। कंपनी ने अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने के लिए कंपनी-स्वामित्व और फ्रैंचाइजी मॉडल का मिला-जुला स्ट्रक्चर अपनाया है। वर्तमान में करीब 180 आउटलेट्स में से 40 कंपनी के पास हैं।

एनटीपीसी ने लिस्टेड कंपनी के प्रोजेक्ट को किया रद्द, अब शेयर पर निवेशकों की होगी नजर

नईदिल्ली, एजेंसी। एनटीपीसी ने जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, एनटीपीसी ने महाराष्ट्र के मौदा सुपर थर्मल पावर प्रगति हासिल करने में विफलता के कारण 400 मेगावाट-घंटा परियोजना के लिए जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया है। यह ठेका जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स को दिया गया था। अब सोमवार को एनटीपीसी और जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर की कीमत शुक्रवार को करीब 2 पर्सेंट गिरकर 324 रुपये पर थी। जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स के शेयर की बात करें तो 825 पर था। इसका कुल मूल्य 413.37 करोड़ रुपये था।

यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्छस्पर परियोजना थी और राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप इसे 15 महीने में पूरा किया जाना था। लेकिन परियोजना की महत्वपूर्ण गतिविधियों में काफी देरी हुई। एनटीपीसी ने कहा कि उसने जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स को तत्काल

टाटा स्टील के ब्रिटेन कारोबार पर आया बड़ा अपडेट, शेयर में सोमवार को होगी हलचल

नईदिल्ली, एजेंसी। अगर पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, टाटा स्टील के ब्रिटेन कारोबार को लेकर नया अपडेट आया है। टाटा स्टील ने ब्रिटेन में अपने पोर्ट टैलबोट स्टील प्लांट के बदलाव के लिए सरकार से सैकड़ों मिलियन पाउंड की अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा स्टील ने हाल के हफ्तों में ब्रिटेन के बिजनेस, इनोवेशन एंड साइंस विभाग के अधिकारियों से अतिरिक्त सरकारी सहायता को लेकर बातचीत की है। यह मांग ऐसे समय आई है जब पोर्ट टैलबोट में नए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाने की परियोजना में देरी हो रही है और इसकी लागत बढ़ने का दावा है। बता दें कि पोर्ट टैलबोट प्लांट के लिए टाटा स्टील ने कुल 1.25 अरब पाउंड के निवेश की योजना बनाई थी। इस निवेश का उद्देश्य पुराने फर्नेस फर्नेस आधारित उत्पादन की जगह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाकर कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्टील उत्पादन व्यवस्था तैयार करना है। पोर्ट टैलबोट में निवेश ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन को बनाए रखने और इसे कम उत्सर्जन वाली तकनीक की ओर ले जाने के लिए अहम है। हालांकि, अगर ब्रिटेन सरकार अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराती है तो इससे सरकार की औद्योगिक नीति और संकट में फंसे स्टील उद्योग को लेकर उसके रुख पर बहस फिर तेज हो सकती है।

नईदिल्ली, एजेंसी। अगर पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, टाटा स्टील के ब्रिटेन कारोबार को लेकर नया अपडेट आया है। टाटा स्टील ने ब्रिटेन में अपने पोर्ट टैलबोट स्टील प्लांट के बदलाव के लिए सरकार से सैकड़ों मिलियन पाउंड की अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा स्टील ने हाल के हफ्तों में ब्रिटेन के बिजनेस, इनोवेशन एंड साइंस विभाग के अधिकारियों से अतिरिक्त सरकारी सहायता को लेकर बातचीत की है। यह मांग ऐसे समय आई है जब पोर्ट टैलबोट में नए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाने की परियोजना में देरी हो रही है और इसकी लागत बढ़ने का दावा है। बता दें कि पोर्ट टैलबोट प्लांट के लिए टाटा स्टील ने कुल 1.25 अरब पाउंड के निवेश की योजना बनाई थी। इस निवेश का उद्देश्य पुराने फर्नेस फर्नेस आधारित उत्पादन की जगह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाकर कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्टील उत्पादन व्यवस्था तैयार करना है। पोर्ट टैलबोट में निवेश ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन को बनाए रखने और इसे कम उत्सर्जन वाली तकनीक की ओर ले जाने के लिए अहम है। हालांकि, अगर ब्रिटेन सरकार अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराती है तो इससे सरकार की औद्योगिक नीति और संकट में फंसे स्टील उद्योग को लेकर उसके रुख पर बहस फिर तेज हो सकती है।

नईदिल्ली, एजेंसी। अगर पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, टाटा स्टील के ब्रिटेन कारोबार को लेकर नया अपडेट आया है। टाटा स्टील ने ब्रिटेन में अपने पोर्ट टैलबोट स्टील प्लांट के बदलाव के लिए सरकार से सैकड़ों मिलियन पाउंड की अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा स्टील ने हाल के हफ्तों में ब्रिटेन के बिजनेस, इनोवेशन एंड साइंस विभाग के अधिकारियों से अतिरिक्त सरकारी सहायता को लेकर बातचीत की है। यह मांग ऐसे समय आई है जब पोर्ट टैलबोट में नए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाने की परियोजना में देरी हो रही है और इसकी लागत बढ़ने का दावा है। बता दें कि पोर्ट टैलबोट प्लांट के लिए टाटा स्टील ने कुल 1.25 अरब पाउंड के निवेश की योजना बनाई थी। इस निवेश का उद्देश्य पुराने फर्नेस फर्नेस आधारित उत्पादन की जगह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाकर कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्टील उत्पादन व्यवस्था तैयार करना है। पोर्ट टैलबोट में निवेश ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन को बनाए रखने और इसे कम उत्सर्जन वाली तकनीक की ओर ले जाने के लिए अहम है। हालांकि, अगर ब्रिटेन सरकार अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराती है तो इससे सरकार की औद्योगिक नीति और संकट में फंसे स्टील उद्योग को लेकर उसके रुख पर बहस फिर तेज हो सकती है।

नईदिल्ली, एजेंसी। अगर पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, टाटा स्टील के ब्रिटेन कारोबार को लेकर नया अपडेट आया है। टाटा स्टील ने ब्रिटेन में अपने पोर्ट टैलबोट स्टील प्लांट के बदलाव के लिए सरकार से सैकड़ों मिलियन पाउंड की अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा स्टील ने हाल के हफ्तों में ब्रिटेन के बिजनेस, इनोवेशन एंड साइंस विभाग के अधिकारियों से अतिरिक्त सरकारी सहायता को लेकर बातचीत की है। यह मांग ऐसे समय आई है जब पोर्ट टैलबोट में नए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाने की परियोजना में देरी हो रही है और इसकी लागत बढ़ने का दावा है। बता दें कि पोर्ट टैलबोट प्लांट के लिए टाटा स्टील ने कुल 1.25 अरब पाउंड के निवेश की योजना बनाई थी। इस निवेश का उद्देश्य पुराने फर्नेस फर्नेस आधारित उत्पादन की जगह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाकर कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्टील उत्पादन व्यवस्था तैयार करना है। पोर्ट टैलबोट में निवेश ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन को बनाए रखने और इसे कम उत्सर्जन वाली तकनीक की ओर ले जाने के लिए अहम है। हालांकि, अगर ब्रिटेन सरकार अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराती है तो इससे सरकार की औद्योगिक नीति और संकट में फंसे स्टील उद्योग को लेकर उसके रुख पर बहस फिर तेज हो सकती है।

नईदिल्ली, एजेंसी। अगर पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, टाटा स्टील के ब्रिटेन कारोबार को लेकर नया अपडेट आया है। टाटा स्टील ने ब्रिटेन में अपने पोर्ट टैलबोट स्टील प्लांट के बदलाव के लिए सरकार से सैकड़ों मिलियन पाउंड की अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा स्टील ने हाल के हफ्तों में ब्रिटेन के बिजनेस, इनोवेशन एंड साइंस विभाग के अधिकारियों से अतिरिक्त सरकारी सहायता को लेकर बातचीत की है। यह मांग ऐसे समय आई है जब पोर्ट टैलबोट में नए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाने की परियोजना में देरी हो रही है और इसकी लागत बढ़ने का दावा है। बता दें कि पोर्ट टैलबोट प्लांट के लिए टाटा स्टील ने कुल 1.25 अरब पाउंड के निवेश की योजना बनाई थी। इस निवेश का उद्देश्य पुराने फर्नेस फर्नेस आधारित उत्पादन की जगह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाकर कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्टील उत्पादन व्यवस्था तैयार करना है। पोर्ट टैलबोट में निवेश ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन को बनाए रखने और इसे कम उत्सर्जन वाली तकनीक की ओर ले जाने के लिए अहम है। हालांकि, अगर ब्रिटेन सरकार अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराती है तो इससे सरकार की औद्योगिक नीति और संकट में फंसे स्टील उद्योग को लेकर उसके रुख पर बहस फिर तेज हो सकती है।

नईदिल्ली, एजेंसी। अगर पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, टाटा स्टील के ब्रिटेन कारोबार को लेकर नया अपडेट आया है। टाटा स्टील ने ब्रिटेन में अपने पोर्ट टैलबोट स्टील प्लांट के बदलाव के लिए सरकार से सैकड़ों मिलियन पाउंड की अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा स्टील ने हाल के हफ्तों में ब्रिटेन के बिजनेस, इनोवेशन एंड साइंस विभाग के अधिकारियों से अतिरिक्त सरकारी सहायता को लेकर बातचीत की है। यह मांग ऐसे समय आई है जब पोर्ट टैलबोट में नए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाने की परियोजना में देरी हो रही है और इसकी लागत बढ़ने का दावा है। बता दें कि पोर्ट टैलबोट प्लांट के लिए टाटा स्टील ने कुल 1.25 अरब पाउंड के निवेश की योजना बनाई थी। इस निवेश का उद्देश्य पुराने फर्नेस फर्नेस आधारित उत्पादन की जगह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाकर कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्टील उत्पादन व्यवस्था तैयार करना है। पोर्ट टैलबोट में निवेश ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन को बनाए रखने और इसे कम उत्सर्जन वाली तकनीक की ओर ले जाने के लिए अहम है। हालांकि, अगर ब्रिटेन सरकार अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराती है तो इससे सरकार की औद्योगिक नीति और संकट में फंसे स्टील उद्योग को लेकर उसके रुख पर बहस फिर तेज हो सकती है।

नईदिल्ली, एजेंसी। अगर पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, टाटा स्टील के ब्रिटेन कारोबार को लेकर नया अपडेट आया है। टाटा स्टील ने ब्रिटेन में अपने पोर्ट टैलबोट स्टील प्लांट के बदलाव के लिए सरकार से सैकड़ों मिलियन पाउंड की अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा स्टील ने हाल के हफ्तों में ब्रिटेन के बिजनेस, इनोवेशन एंड साइंस विभाग के अधिकारियों से अतिरिक्त सरकारी सहायता को लेकर बातचीत की है। यह मांग ऐसे समय आई है जब पोर्ट टैलबोट में नए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाने की परियोजना में देरी हो रही है और इसकी लागत बढ़ने का दावा है। बता दें कि पोर्ट टैलबोट प्लांट के लिए टाटा स्टील ने कुल 1.25 अरब पाउंड के निवेश की योजना बनाई थी। इस निवेश का उद्देश्य पुराने फर्नेस फर्नेस आधारित उत्पादन की जगह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाकर कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्टील उत्पादन व्यवस्था तैयार करना है। पोर्ट टैलबोट में निवेश ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन को बनाए रखने और इसे कम उत्सर्जन वाली तकनीक की ओर ले जाने के लिए अहम है। हालांकि, अगर ब्रिटेन सरकार अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराती है तो इससे सरकार की औद्योगिक नीति और संकट में फंसे स्टील उद्योग को लेकर उसके रुख पर बहस फिर तेज हो सकती है।

नईदिल्ली, एजेंसी। अगर पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, टाटा स्टील के ब्रिटेन कारोबार को लेकर नया अपडेट आया है। टाटा स्टील ने ब्रिटेन में अपने पोर्ट टैलबोट स्टील प्लांट के बदलाव के लिए सरकार से सैकड़ों मिलियन पाउंड की अतिरिक्त वित्तीय मदद मांगी है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा स्टील ने हाल के हफ्तों में ब्रिटेन के बिजनेस, इनोवेशन एंड साइंस विभाग के अधिकारियों से अतिरिक्त सरकारी सहायता को लेकर बातचीत की है। यह मांग ऐसे समय आई है जब पोर्ट टैलबोट में नए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाने की परियोजना में देरी हो रही है और इसकी लागत बढ़ने का दावा है। बता दें कि पोर्ट टैलबोट प

'मेरे सपनों का भारत' प्रतियोगिता के होनहार छात्र-छात्राएं हुए सम्मानितके साथ होगा समापन

नई पीढ़ी में देशभक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाना ही सेवा संकल्प का मुख्य उद्देश्य: राज्यमंत्री गौर

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि 'आज की नई पीढ़ी के दिल में अपने देश के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' का मुख्य उद्देश्य हमारे बच्चों और युवाओं में आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है, जिससे वे एक मजबूत भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।' राज्यमंत्री श्रीमती गौर सोमवार को भोपाल के गोविंदपुरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आनंद नगर में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित 'मेरे सपनों का भारत' चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था की सराहना की और बच्चों की प्रतिभा का



उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश को मिली नई दिशा राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत विकास के नए आयाम तय कर रहा है। आज पूरा देश उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता अभियान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक साफ-सुथरा समाज ही

एक स्वस्थ और मजबूत देश का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है और उनके विचारों को अपनाकर ही हम एक समृद्ध भारत बना सकते हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कार ही हमारी असली पहचान राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने भारतीय संस्कारों और मूल्यों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि



हमारी संस्कृति और अच्छे संस्कार ही पूरी दुनिया में भारत को एक अलग और खास पहचान दिलाते हैं। शिक्षकों और गुरुओं के सही मार्गदर्शन में आज का हर बच्चा आत्मविश्वास से भरा हुआ है और देश की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। समारोह में 'मेरे सपनों का भारत' विषय पर आयोजित चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन

करने वाले प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्री संतोष ग्वाला, पार्षद श्रीमती छाया ठाकुर, श्रीमती ममता विश्वकर्मा, प्राचार्य श्री पुष्पा, श्री अशोक गुप्ता, श्री प्रदीप लोधी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।



■ एक सत बुलेटिन, कटनी।

शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के संकल्प के साथ नगर पालिक निगम कटनी का सेवा संकल्प अभियान लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। निगम की जागरूकता टीम ने विभिन्न वाडों में घर-घर दस्तक देकर नागरिकों को कचरा प्रबंधन, स्वच्छता व्यवस्था और जिम्मेदार नागरिकता का पाठ पढ़ाया। अभियान के दौरान लोगों को समझाया गया कि स्वच्छता केवल सड़कों और गलियों की सफाई तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी असली शुरुआत हर घर से कचरे के सही पृथक्करण के साथ होती है। इसी क्रम में वाड क्रमांक 29 चंदी की दफाई और वाड क्रमांक 28 नेहरू वाड में निगम की टीम ने घर-घर

संपर्क कर नागरिकों को चार बिन कचरा पृथक्करण व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया। टीम ने गीला, सूखा, सैनटरी तथा विशेष देखभाल वाले कचरे को अलग-अलग रखने की जानकारी देते हुए निर्धारित संग्रहण व्यवस्था के माध्यम से ही कचरा देने की समझाइश दी। जागरूकता टीम ने नागरिकों को बताया कि कचरे को स्रोत पर ही अलग करने से उसके उचित निस्तारण में मदद मिलती है और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं वाड क्रमांक 40 एमईएस कॉलोनी में कचरा प्रबंधन एवं उचित निस्तारण को लेकर विशेष जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई।

रेलवे महाप्रबंधक ने सागर, दमोह स्टेशन एवं कटनी मुड़वारा-सागर रेलखंड का किया निरीक्षण



■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री दिलीप कुमार सिंह ने सोमवार, 21 सितम्बर 2026 को सागर एवं दमोह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कटनी मुड़वारा-सागर रेलखंड का रियर विंडो निरीक्षण कर रेल अधोसंरचना, संरक्षा एवं परिचालन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाप्रबंधक ने स्पेशल निरीक्षण यान से रेलखंड का निरीक्षण करते हुए रेल पथ, सिग्नलिंग, पुल-पुलियों, ओएचई तथा अन्य महत्वपूर्ण संरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अनुरक्षण एवं अधोसंरचना कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संरक्षा मानकों का पूर्ण पालन, उच्च गुणवत्ता तथा समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सागर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की समीक्षा सागर स्टेशन के निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, परिचालन एवं संरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के

दौरान महाप्रबंधक ने सागर की सांसद माननीया श्रीमती लता वानखेडे से सौजन्य भेंट की तथा स्टेशन विकास, यात्री सुविधाओं एवं क्षेत्र की रेल आवश्यकताओं से संबंधित सुझाव प्राप्त किए। सांसद महोदया ने महाप्रबंधक के साथ स्टेशन एवं रेलखंड पर चल रहे विभिन्न अनुरक्षण एवं अधोसंरचना कार्यों का संयुक्त निरीक्षण भी किया। महाप्रबंधक ने प्राप्त सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

आरओबी की संरक्षा व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा महाप्रबंधक ने सागर-नारियावली के मध्य स्थित आरओबी का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध संरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्धारित संरक्षा मानकों एवं नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दमोह स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों की समीक्षा इसके पश्चात महाप्रबंधक ने दमोह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को कार्यों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटरों का औचक निरीक्षण



भिण्ड। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड डॉ. जे.एस. यादव के निर्देशन में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत भिण्ड शहरी क्षेत्र में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में डॉ. आर.एस. सैमिल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1 एवं लिपिक श्री राजदीप यादव द्वारा विभिन्न अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण किया गया पारस अल्ट्रासाउंड सेंटर, संचालक डॉ. हिमांशु भारद्वाज, अस्पताल के सामने, लश्कर रोड, भिण्ड।

पीएम कुसुम बी योजना से अमायन के कृषक प्रताप सिंह को मिली ऊर्जा सुरक्षा

■ एक सत बुलेटिन, भिण्ड

भिण्ड जिले के अमायन निवासी कृषक प्रताप सिंह को पीएम कुसुम बी योजना अंतर्गत स्थापित सोलर पंप से खेत में सिंचाई का विश्वसनीय विकल्प मिला है। इनके खेत में स्थापित रोटोमैक कंपनी के 3 एचपी क्षमता के सोलर पम्प ने इन्हें ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। कृषक प्रताप सिंह बताते हैं कि अपने 1.5 बीघा खेत में सिंचाई के लिए पहले अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना पड़ता था जिसका वार्षिक व्यय 12-13 हजार रुपए होता था। इतने व्यय के बावजूद बिजली की निर्बाध आपूर्ति नहीं होने से समय से सिंचाई नहीं कर पाते थे। आवेदन स्वीकृत होने पर उन्होंने सोलर पंप की स्थापना पर लगभग 21 हजार रुपए का अंशदान दिया। वर्ष 2025 में सोलर पंप लगने के बाद बिजली कनेक्शन पर व्यय होने वाली राशि की अब बचत हो रही है और वे आसपास के कृषकों को भी सिंचाई में मदद कर रहे हैं। कृषक प्रताप सिंह इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन



यादव को धन्यवाद देते हैं। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार की पीएम कुसुम बी योजना को प्रदेश में 'प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना' के नाम से संचालित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 7.5 एचपी तक क्षमता वाले ऑफ-ग्रिड सोलर पम्प की स्थापना पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। सोलर पंप की वास्तविक लागत का केवल 10 प्रतिशत कृषक को वहन करना होता है।

सोशल मीडिया की सुर्खियों से बाहर निकले महापौर जनसुनवाई, दिखे समस्याओं का समाधान : नेता प्रतिपक्ष रागिनी गुप्ता

कटनी। नगर पालिक निगम कटनी में महापौर द्वारा आयोजित की जा रही जनसुनवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद रागिनी मनोज गुप्ता ने तीखा रुख अपनाते हुए व्यवस्था की कार्यगणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल तस्वीरें खिंचवाना और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरना नहीं, बल्कि शहर की जनता की समस्याओं का वास्तविक और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना होना चाहिए। यदि जनसुनवाई के बाद भी नागरिक अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर निगम कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं, तो ऐसी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। नेता प्रतिपक्ष रागिनी गुप्ता ने कहा कि नगर निगम में प्रत्येक सप्ताह बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतें और उम्मीदें लेकर जनसुनवाई में पहुंचते हैं। लेकिन पूर्व में प्राप्त शिकायतों में कितनों का निराकरण हुआ और कितनी समस्याएं अब भी लंबित हैं, इसका पारदर्शी आंकड़ा जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के अनेक क्षेत्रों में सड़क, नाली, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।



गुड़िया की शादी में रिश्तों और परंपराओं का रंग

भारत भवन में आयोजित तीन दिवसीय प्रणति समारोह का हुआ समापन

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

बहुकला केंद्र भारत भवन में ब.व. कारंत की स्मृति में आयोजित तीन दिवसीय 'प्रणति समारोह' का समापन सोमवार को नाटक 'गुड़िया की शादी' के मंचन के साथ हुआ। मद्र नाट्य विद्यालय, भोपाल के कलाकारों ने प्रस्तुत इस नाटक का निर्देशन संजय श्रीवास्तव ने किया। अंतिम दिन हुए इस मंचन में कलाकारों ने अभिनय, संवाद और मंचीय गतिविधियों के माध्यम से दर्शकों के सामने विवाह संस्था और उससे जुड़े सामाजिक व्यवहारों को रोचक ढंग से रखने का प्रयास किया। मंचित नाटक एक

सहज और धरेलू संसार का संकेत देता है, लेकिन मंच पर यह संसार केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता। नाटक सामाजिक रिश्तों, पारिवारिक अपेक्षाओं और विवाह को लेकर बनी धारणाओं को सामने लाता है। कहानी के घटनाक्रम में हास्य और व्यंग्य के प्रसंगों के साथ ऐसे क्षण भी आते हैं, जो दर्शकों को सामाजिक व्यवहार और रिश्तों की वास्तविकता पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। यही नाटक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही कि सामान्य-सी दिखाई देने वाली घटना के माध्यम से व्यापक सामाजिक संदर्भ निर्मित किया गया। निर्देशक संजय श्रीवास्तव ने नाटक



को सहज गति देने की कोशिश की। मंच पर दृश्यों का संयोजन ऐसा रहा कि कथा

एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग की ओर बढ़ती रही और दर्शकों की रुचि बनी रही। संवादों

के जरिए परिस्थितियों को उभारने के साथ-साथ हास्य को भी स्थान दिया गया। निर्देशन में नाटक की सामूहिकता विशेष रूप से दिखाई दी। कलाकारों के बीच दिखा बेहतर तालमेल मद्र नाट्य विद्यालय के कलाकारों के अभिनय की बात करें तो उनकी प्रस्तुति में रंगमंचीय प्रशिक्षण की झलक दिखाई दी। कलाकारों ने अपने-अपने पात्रों की प्रकृति के अनुरूप संवाद अदायगी और शारीरिक हाव-भाव का इस्तेमाल किया। विशेष रूप से हास्यपूर्ण स्थितियों में कलाकारों की टाइमिंग और संवादों की प्रस्तुति ने वातावरण को हल्का बनाया। वहीं गंभीर प्रसंगों में अभिनय

अपेक्षाकृत संयमित रहा। सामूहिक दृश्यों में कलाकारों के बीच तालमेल भी मंचन की एक उल्लेखनीय विशेषता रहा। नाटक की मंच-सज्जा और प्रकाश व्यवस्था ने कथा के वातावरण को स्थापित करने में सहयोग किया। सीमित साधनों के बीच मंच का उपयोग प्रभावी ढंग से किया गया। दृश्यों के परिवर्तन में अनावश्यक जटिलता नहीं दिखाई दी, जिससे कथा की गति प्रभावित नहीं हुई। संवादों के साथ मंचीय गतिविधियों का संतुलन भी प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाने में सहायक रहा। नाटक का संगीत और ध्वनि प्रभाव भी वातावरण निर्माण में उपयोगी रहे।

बघेली स्थापत्य कला की झलक के साथ-साथ आधुनिक स्थापत्य की भी झलक है

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सेवा संकल्प अभियान में किया त्यंकट भवन का भ्रमण



■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रारंभ हुए 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत रीवा के ऐतिहासिक व्यंकट भवन का भ्रमण किया। उप मुख्यमंत्री ने व्यंकट भवन में पुरातत्व

विभाग द्वारा किए जा रहे सौन्दर्यीकरण का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन 17 सितम्बर से सेवा संकल्प अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार हमारी प्राचीन विरासतों को संरक्षित करने का प्रयास



किया जा रहा है। व्यंकट भवन रीवा ही नहीं पूरे विन्ध्य क्षेत्र की ऐतिहासिक और गौरवमयी विरासत है। इसमें बघेली स्थापत्य कला की झलक के साथ-साथ आधुनिक स्थापत्य की भी झलक है। इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।

इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाण्डेय

एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्य में जनहित और विकास कार्यों को गति देने के क्रम में, उप मुख्यमंत्री ने आज 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत ऐतिहासिक व्यंकट भवन का औचक भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने भवन की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

नवकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण से किफायती बिजली खरीद विषय

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के तत्वावधान में और प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की सहभागिता से 22 सितंबर को भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण से किफायती बिजली खरीद विषय पर एक दिवसीय क्षेत्रीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को भोपाल में प्रातः 10 बजे वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। वर्कशॉप में देश भर के 50 से अधिक डिस्कॉम के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्कशॉप में डायरेक्टर जनरल श्री आलोक कुमार (पूर्व विद्युत सचिव भारत सरकार) मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मनीष सिंह, ऊर्जा सचिव श्री विशेष गढ़वाले, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री अजय गुप्ता, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री अनूप कुमार सिंह सहित ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ



वर्कशॉप में भाग लेंगे। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का शुभारंभ 14 नवंबर 2024 को केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा किया गया। यह एक गैर-लाभकारी संस्था है, जिसका उद्देश्य देश के विद्युत वितरण क्षेत्र को अधिक सशक्त, सक्षम और प्रभावी बनाना है। भारत में डिस्कॉम के लिए विशेष रूप से गठित इस अनूठे साझा मंच के रूप में IDA देश की 34 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं की सेवा करने वाली वितरण कंपनियों की सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करता है। यह मंच आपसी सहयोग, क्षमता निर्माण, नवाचार और नीतिगत पक्षसमर्थन के माध्यम से विद्युत वितरण क्षेत्र के प्रदर्शन और उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

ऑडिट में आपत्ति नहीं लगाने के एवज में रिश्तवत लेते दो आरोपी ट्रेप

■ एक सत बुलेटिन, नरसिंहपुर।

लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सोमवार, 21 सितंबर 2026 को नरसिंहपुर में दो आरोपियों को 8 हजार रुपए की रिश्तवत लेते रगे हाथों पकड़ा। कार्रवाई पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल योगेश देशमुख के निर्देशन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक लोकायुक्त मनोज सिंह के नेतृत्व में की गई। लोकायुक्त के अनुसार ग्राम मेघ, तहसील गोटेगांव निवासी अशोक कुमार पटेल की सेवा सहकारी समिति बरहटा के वर्ष 2025-26 के ऑडिट का कार्य ऑडिट ऑफिसर राजेंद्र सिंह द्वारा किया जा रहा था। आरोप है कि ऑडिट करने और ऑडिट में आपत्ति नहीं लगाने के एवज में राजेंद्र सिंह ने 20 हजार रुपए रिश्तवत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान राजेंद्र सिंह 8 हजार रुपए लेने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद सोमवार को विपणन सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर के कार्यालय में राजेंद्र सिंह की उपस्थिति में सहआरोपी अमित



श्रीवास्तव को 8 हजार रुपए की रिश्तवत लेते हुए लोकायुक्त दल ने रगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजेंद्र सिंह (59), ऑडिट ऑफिसर, कार्यालय उपआयुक्त सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर तथा अमित श्रीवास्तव (34), प्रभारी प्रबंधक, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर के रूप में हुई है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 13(1)बी, 13(2) एवं धारा 61(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में ट्रेप दल के टीएलओ निरीक्षक राहुल गर्जभिए, निरीक्षक जितेंद्र यादव सहित लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा।

भोपाल मंडल में 'कर्मचारी प्रश्नमंच' प्रतियोगिता आयोजित

भोपाल। पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल में 14 से 26 सितंबर 2026 तक राजभाषा पखवाड़ा-2026 का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 21 सितंबर 2026 को मंडल कार्यालय में 'कर्मचारी प्रश्नमंच प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भोपाल मंडल के 30 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रश्नमंच प्रतियोगिता के माध्यम से कर्मचारियों के राजभाषा हिंदी से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के साथ-साथ सामान्य ज्ञान एवं रेलवे से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनकी जानकारी को रोचक एवं सहभागितापूर्ण तरीके से विकसित करने का प्रयास किया गया। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों से विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए।

पर्यावरण संस्कृति ट्रस्ट ने आईएस शिवराज वर्मा को उत्कृष्ट शासन एवं पर्यावरण प्रशासन पुरस्कार से किया सम्मानित

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

पर्यावरण संस्कृति संरक्षण एवं मानव कल्याण ट्रस्ट, भोपाल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा को उत्कृष्ट शासन एवं पर्यावरण प्रशासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ट्रस्ट की ओर से सुशील कुमार जैन, विनय जैन बावड़ी खेड़ा एवं मोहन सोनी ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर श्री वर्मा को ग्वालियर से बड़वानी और भोपाल तक की प्रशासनिक यात्रा में जनसेवा, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी से जुड़े कार्यों का उल्लेख किया गया। कहा गया कि प्रशासनिक पद केवल अधिकारों के निर्वहन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की संवेदना पहुंचाने का माध्यम भी है। ग्वालियर में आनंद विभाग से जुड़े दायित्व के दौरान आनंद क्लबों की स्थापना और विस्तार तथा साइकिल रैली जैसे आयोजनों को सामाजिक संदेशों से जोड़ने के प्रयास किए गए। इसके माध्यम से नागरिकों को



सकारात्मक गतिविधियों और सामाजिक सहभागिता से जोड़ने पर जोर दिया गया। बड़वानी में कलेक्टर के रूप में कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, मातृ-शिशु सुरक्षा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण तथा आदिवासी क्षेत्रों तक शासन की पहुंच से जुड़े अनेक प्रयास किए गए। मिशन उम्मीद के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था को स्थानीय जनभागीदारी से मजबूत

किया गया। ममता दल, पोषण पुनर्वास केंद्रों में खिलौना बैंक तथा जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए पहुंच अभियान जैसी पहल भी की गई। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़वानी की एक बंजर पहाड़ी को शिवकुंज के रूप में विकसित कर बड़े स्तर पर पौधरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त चार अन्य पहाड़ियों पर मिलाकर लगभग 70 हजार पौधे लगाए गए, जो अब वृक्षों का रूप ले चुके हैं।

मंडल के बीना, रानी कमलापति एवं इटारसी स्टेशनों के यात्रियों को मिलेगी सुविधा का लाभ

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा अतिरिक्त यात्री सुविधा के लिए प्रयागराज से हडपसर नगर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 04107 प्रयागराज से हडपसर पूजा स्पेशल ट्रेन दिनांक 21 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2026 तक प्रत्येक बुधवार को प्रयागराज स्टेशन से रात 10:20 बजे प्रस्थान कर बीना 23.35 बजे, अगले दिन रानी कमलापति 02.00 बजे, इटारसी 03.35 बजे एवं आगमन कर गंतव्य स्टेशन चल कर हडपसर 19.30 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04108 प्रयागराज से



हडपसर स्पेशल ट्रेन दिनांक 22 अक्टूबर से 19 नवम्बर 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को हडपसर स्टेशन से रात 22:40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन प्रयागराज 06.30 बजे, इटारसी 12.20, रानी कमलापति 14.15 बजे एवं बीना 16.45 बजे आगमन कर प्रयागराज सुबह 06.30 बजे पहुंचेगी। कोच संरचना- इस स्पेशल गाड़ी में 2 एसएलआरबी, 6 सामान्य श्रेणी, 12 स्लीपर, 1 थर्ड एसी सहित कुल 21 कोच होंगे। उद्घाटन स्टेशन- प्रयागराज, शंकरगढ़, डभौरा, मानिकपुर, चित्रकूट धाम, बांदा जंक्शन, महोबा, खजुराहो, दरियागंज, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, भुसावल जंक्शन, मनमाड, कोपरगाँव, बेलापुर, अहिल्यानगर, दौंड कॉर्ड लाइन, हडपसर।

भोपाल देहात पुलिस की गणेश उत्सव के अवसर पर सौगात

भोपाल। आगामी त्रौहार पर्व को दृष्टिगत रखते हुए आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा के साथ-साथ उनकी गुम हुई संपत्ति की बरामदगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भोपाल देहात पुलिस द्वारा 15 दिवसीय विशेष अभियान 'ऑपरेशन विश्वास' संचालित किया गया। प्रमोद कुमार सोनकर के मार्गदर्शन व समस्त एसडीओपी भोपाल देहात के पर्यवेक्षण में भोपाल साइबर एवं जिले के समस्त थाना पुलिस द्वारा समन्वित रूप से गुम मोबाइल फोन की तलाश एवं बरामदगी हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

विनय मेहर की बिटिया मानवी मेहर का प्रथम जन्मोत्सव श्रद्धा सेवा और जनआशीर्वाद के साथ मनाया गया

■ एक सत बुलेटिन, बैरसिया।

जिला पंचायत सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा नेता विनय मेहर की लाडली बिटिया मानवी मेहर का प्रथम जन्मोत्सव रविवार को बैरसिया स्थित पार्क सिटी निवास पर श्रद्धा सेवा और जनआशीर्वाद के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री खाटू श्याम का भव्य दरबार सजाया गया, जहां देर रात तक श्याम प्रेमियों ने भजनों का जमकर आनंद लिया। जन्मोत्सव कार्यक्रम में 11 ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तितवाचन कर बिटिया मानवी को आशीर्वाद प्रदान किया गया। वहीं सामाजिक सरोकार के तहत दिव्यांगजनों को साइकिल का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्नेह एवं आशीर्वाद भी मानवी मेहर को प्राप्त हुआ। उनके द्वारा चलाए जा रहे 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत बेटी मानवी के नाम से



पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर विनय मेहर ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से समाजसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके का भी मानवी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। विनय मेहर ने कहा कि बहन संपतिया उइके का उन्हें हमेशा छोटे भाई की तरह स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहा है। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने विनय मेहर की माता का पुष्पमालाओं से स्वागत कर सम्मान किया।

संभागायुक्त ने की राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा

राजस्व प्रकरणों का तत्परता से करें निराकरण : संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें, कार्य में कोई लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को आयुक्त कार्यालय में वीसी के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के साथ राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व श्रीमती भारती देवी मिश्रा उपस्थित थे। संभागायुक्त श्री शर्मा ने वीसी के माध्यम से राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि

मुख्यमंत्री जन अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा प्रबंधन में दर्ज प्रकरणों के समय - 7 मा बाहर एवं 50 दिवस से अधिक की शिकायतों एवं शिविर वार दर्ज शिकायतों का निराकरण करें। साथ प्राप्त शिकायतों के प्रतिवेदन नियत समय में दर्ज करवाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल जिले में आरसीएमएस पोर्टल पर सोमवार की स्थिति में समय- सीमा बाहर न्यायालय तहसीलदार कोलार में 9 प्रकरण, गोविंदपुरा में 01, न्यायालय तहसीलदार वृत्त 01, न्यायालय तहसीलदार वृत्त 01, नयाब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार में 05 प्रकरण दर्ज हैं। विदिशा जिले की कुरवाई तहसील में 02 प्रकरण लंबित पाए गए। इस पर संभागायुक्त ने संबंधित नोडल



अधिकारी को तहसीलदार एवं नयाब तहसीलदार का लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम के नियमानुसार एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। विदिशा जिले की कुरवाई तहसील में 02 प्रकरण लंबित पाए गए। इस पर संभागायुक्त ने संबंधित नोडल अधिकारी को तहसीलदार एवं नयाब तहसीलदार का लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम के नियमानुसार एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। संभागायुक्त श्री शर्मा ने बैठक में उपायुक्त राजस्व को संभाग के सभी जिलों में नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के समय - सीमा बाहर प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए संभाग के

सभी जिलों में फोर्स क्लोज शिकायतों के हितग्राहियों से चर्चा करने के निर्देश भी दिए। संभागायुक्त श्री शर्मा ने बैठक में सभी जिलों में प्रशासनिक कसावट, कार्यालयीन काम-काज में पारदर्शिता, समयबद्ध और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति विकसित करने एवं संभाग के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिजल्ट ऑरिएटेड कार्य प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिलों में बेहतर समन्वय, नियमित समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वहन और जनहित की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य संस्कृति को अपनाएं।